

संस्करण : मुंबई

वर्ष : 11

अंक : 46

पृष्ठ : 8

मूल्य : 2.00

रविवार, 22 फरवरी, 2026

# मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित



3 'माझी वसुंधरा' राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण ... 4 राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के वर्षपर्यंत... 7 क्रिकेट के बाद हॉकी भी बर्बाद करने की ...

## संक्षिप्त न्यूज

**कर्नाटक के भाजपा विधायक रिश्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, गिरफ्तार**

बेंगलूरु। कर्नाटक के शिरहट्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चंद्र लामणि को कर्नाटक लोकायुक्त ने कथित तौर पर 5 लाख रुपये की रिश्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यह राशि कथित तौर पर 11 लाख रुपये की कुल मांग का हिस्सा थी। अधिकारियों ने बताया कि लामणि को पहले एक गुप्त ऑपरेशन के बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और उसके बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में उनके दो निजी सहायकों को भी हिरासत में लिया गया है। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, गडग जिले में सिंचाई विभाग की एक लघु परियोजना से संबंधित स्वीकृतियों को जुगम बनाने के लिए कथित तौर पर रिश्त मांगी गई थी। इस कार्य में सड़क के दोनों किनारों पर एक रिटेनिंग दीवार का निर्माण शामिल था, जिसे एक ठेकेदार को सौंपा गया था। गडग निवासी प्रथम श्रेणी के ठेकेदार विजय पुजार ने भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों से संपर्क किया, क्योंकि परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी दिलाने के बदले उनसे कथित तौर पर 11 लाख रुपये मांगे गए थे। शिकायत की पुष्टि करने के बाद, लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार को जाल बिछाया। इस कार्रवाई के दौरान, लामानी को कथित तौर पर मांगी गई राशि से 5 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया। यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस की एक टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में की। अधिकारियों ने बताया कि कानूनी अनुपालन निश्चित करने के लिए यह कार्रवाई उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई।

## अब भारत में बनेंगे चिप्स!

# पीएम मोदी ने रखी एचसीएल-फॉक्सकॉन यूनिट की नींव, चीन को मिलेगी टक्कर?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एचसीएल-फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर संयंत्र का शिलान्यास किया। उन्होंने इसे चिप उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगी, जिससे नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत को चिप उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना होगा और देश में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है—इस पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि यह गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश भारत के सेमीकंडक्टर सिस्टम का एक प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में एचसीएल-फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के शिलान्यास समारोह में भाग लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भी सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित होती है, वहां डिजाइन केंद्र उभरते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित होते हैं और नवाचार में तेजी आती है। उन्होंने आज संपन्न हुए इंडिया



एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि आज भारत विकास के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। मैंने लाल किले से भी कहा है कि भारत के पास रुकने या धीमा होने का समय नहीं है। 2026 की शुरुआत से ही भारत ने अपनी प्रगति को गति दी है और अब यह सप्ताह भी भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वैश्विक एआई के प्रभाव शिखर सम्मेलन के लिए विश्व भर के राष्ट्राध्यक्ष और प्रौद्योगिकी नेता दिल्ली में एकत्रित हुए। इस शिखर सम्मेलन में विश्व ने भारत की एआई क्षमता को देखा, हमारे दृष्टिकोण को समझा और उसकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशक भारत के लिए 'तकनीकी क्रांति' का दशक है। इस दशक में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत जो कुछ भी कर रहा है, वह 21वीं सदी में हमारी शक्ति का आधार बनेगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत ने भले ही देर से शुरुआत की हो, लेकिन आज हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने अब तक अपने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 सेमीकंडक्टर निर्माण और पैकेजिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से चार इकाइयों बहुत जल्द उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता के भविष्य

को आकार देने वाली हर तकनीक में भारत आज अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। एक विज्ञापित में कहा गया है कि एचसीएल-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए भारत को एक विश्वस्तरीय वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यीडा में स्थित यह आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) संयंत्र इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संशोधित सेमीकंडक्टर असंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) योजना के तहत 3,700 करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश के साथ स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना चार लू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने, आयात पर निर्भरता कम करने और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।

असम में पहली बार हुई सीआरपीएफ स्थापना दिवस परेड में बोले शाह

## '31 मार्च तक देश से खत्म होगा नक्सलवाद'

दिसपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस परेड का असम में पहली बार आयोजन होना पूर्णतः पूर्वोत्तर के लिए गर्व का क्षण है। गुवाहाटी में आयोजित परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 86 साल के इतिहास में पहली बार सीआरपीएफ की रेजिंग डे परेड पूर्वोत्तर में हो रही है, जो क्षेत्र के महत्व को दर्शाता है। शाह ने बताया कि 2019 में

कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत देश के 17 राज्यों के 334 ब्लॉकों और करीब 1,954 गांवों के साथ-साथ असम के 140 सीमावर्ती गांवों में विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। **अवैध अतिक्रमण को बताई सबसे बड़ी समस्या** अमित शाह ने असम में अवैध अतिक्रमण को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि कई गांवों की जमीन पर अतिक्रमण



निर्णय लिया गया था कि यह वार्षिक परेड देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित की जाएगी।

**31 मार्च तक देश से नक्सल समस्या का होगा सफाया** परेड को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां पत्थरबाजी की घटनाओं की संख्या घटकर शून्य हो गई है, इसके अलावा मणिपुर में जातीय हिंसा से निपटने और केवल तीन वर्षों में माओवादियों की कमर तोड़ने के लिए भी बल को तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं सीआरपीएफ पर भरोसा कर सकता हूँ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम 31 मार्च तक देश से नक्सल समस्या का सफाया कर देंगे।

**वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 की शुरुआत** इससे पहले गृह मंत्री ने कछार जिले के कटिगरा स्थित भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के नतनपुर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए

हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने अतिक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, जिसमें घुसपैठियों की पहचान कर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। **पिछली सरकार पर साधा निशाना** सिलचर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में असम में प्रतिदिन औसतन 14 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ, सैकड़ों पुल बने और चार बड़े नए पुलों का उद्घाटन किया गया। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उसने असम के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया और राज्य की सीमाओं को घुसपैठ 2.0 की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए

## तेलंगाना में चल रहा गजब का ड्रामा, निकाय चुनावों में हारे उम्मीदवार जनता से वसूल रहे चुनाव से पहले दिया गया पैसा और उपहार

हैदराबाद। तेलंगाना के कई नगर निकायों में चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह बाद जो दूधय सामने आ रहे हैं, वह लोकतंत्र के लिए असहज ही नहीं, शर्मनाक भी हैं। राजधानी हैदराबाद से लेकर मेडक मलकाजिरी, खम्मम, सूर्यपेट, पेद्दापल्ली, भद्रादि कोठागुडम, जगत्याल और निजामाबाद जैसे जिलों तक एक अजीबो गरीब पोस्ट पोल ड्रामा चल रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव हार चुके उम्मीदवार घर घर जाकर वह

नकद रकम और उपहार वापस मांग रहे हैं, जो उन्होंने मतदान से पहले बांटे थे। बताया जा रहा है कि 10 फरवरी को मतदान से ठीक पहले कुछ नगरपालिकाओं और वार्डों में प्रति वोट ढाई हजार से तीन हजार रुपये तक बांटे गए। महिला मतदाताओं को प्रेशर कुकर और साड़ियां दी गईं। यह सब खुलेआम हुआ। लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आये तो अब वही उम्मीदवार या उनके परिजन मतदाताओं के दरवाजे खटखटा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने आग में घी का काम किया है। एक वीडियो में एक पुरुष और एक महिला, जिन्हें एक प्रमुख दल से जुड़ा बताया जा रहा है, साड़ियां वापस ले जाते दिख रहे हैं। पूछे जाने पर महिला कहती है कि अगर उन्हें एक वोट मिला तो विपक्ष को दी गई। दूसरे वीडियो में एक महिला, जिसे उम्मीदवार बताया जा रहा है, एक मतदाता पर दबाव बनाती दिखती है कि वह कसम खाकर बताए कि उसने

वोट उसी को दिया। आश्वासन मिलने के बाद वह सूची में नाम के आगे निशान लगाती है। मेडक मलकाजिरी जिले में मतगणना के तुरंत बाद एक उम्मीदवार के घर चर जाकर रकम लौटाने की मांग करने की खबर है। येल्लमपेट नगरपालिका में एक निर्दलीय उम्मीदवार के पति ने कथित रूप से लोगों से कहा कि या तो पैसे लौटाओ या कसम खाकर बताओ कि वोट उनकी पत्नी को दिया था।

## स्वास्थ्य विभाग में 1000 नियुक्तियां, सीएम का दावा- डॉक्टरों समेत 5700 तबादलों में भ्रष्टाचार नहीं

बंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य भर्ती और ट्रांसफर में भ्रष्टाचार को खत्म करना है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में सभी नियुक्तियों और ट्रांसफर अब काउंसिलिंग के माध्यम से किए जा रहे हैं ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। सीएम ने नए भर्ती हुए कर्मचारियों को चेतावनी दी कि किसी भी तरह के ट्रांसफर के लिए किसी के पास न जाए और ट्रांसफर एजेंटों के जाल में फंसने से बचें। कर्नाटक सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि काउंसिलिंग के जरिए अब तक लगभग 5,700 डॉक्टरों का ट्रांसफर किया जा चुका है। नई नियुक्तियां भी इसी प्रक्रिया से की जा रही हैं। किसी को भी पैसे देकर ट्रांसफर या भर्ती कराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सिद्धारमैया ने अपने अनुभव का कया जिक्र

इस दौरान सिद्धारमैया ने अपने अनुभव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 40 साल से ज्यादा मंत्री, विधायक, विपक्षी नेता और मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले यह समस्या इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब ट्रांसफर एजेंटों की संख्या बढ़ रही है। **सीएम ने करीब 1000 कर्मचारियों को बांटे नियुक्ति पत्र**

बता दें कि सीएम सिद्धारमैया ने ये बातें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'अभय हस्त' में कही। इस मौके पर उन्होंने करीब 1,000 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। सीएम ने इन कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि यह नौकरी किसी पेशा नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा का अवसर है। उन्होंने सभी से कहा कि इस विभाग में काम

करते समय मानवता को प्राथमिकता दें, जाति या धर्म की नहीं। सिद्धारमैया ने अपने वादे पूरे करने की बात कही इसके साथ ही सिद्धारमैया ने बताया कि सरकार ने लौटकर वादे के मुताबिक सभी खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये जनता की सेवा के लिए आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने स्वास्थ्य विभाग में मानवता और सेवा के लिए शामिल होने का निर्णय लिया है। यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने का काम है। इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारी अब विभाग में शामिल हो गए हैं और जनता की सेवा में योगदान देना शुरू करेंगे।

## विधानसभा से चुनाव पहले गरमाया भाषा विवाद, उदयनिधि स्टालिन बोले- तमिलनाडु में हिंदी की कोई जगह नहीं

चेन्नई। तमिलनाडु के डिप्टी मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदी भाषा को लेकर फिर साफ और सख्त रुख दोहराया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में हिंदी थोपने का विरोध कोई नया मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लंबे इतिहास और आंदोलन से जुड़ा हुआ है। '1937 के आंदोलन से आज तक वही रुख' उदयनिधि स्टालिन ने बताया कि सबसे पहला हिंदी विरोध आंदोलन 1937-38 में समाज सुधारक पेरियार ने शुरू किया था, जब स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि (कलाइंनार) भी 14 साल की उम्र में तिरुवरूर में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। स्टालिन ने याद दिलाया कि 21 फरवरी 1940 को सरकार को

यह फैसला वापस लेना पड़ा और हिंदी को अनिवार्यता खत्म कर दी गई। 'तमिल को किसी सहारे की जरूरत नहीं' उन्होंने कहा कि कई लोग सवाल उठाते

की जरूरत नहीं है। डिप्टी सीएम ने द्रविड़ आंदोलन की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि डीएमके ही वह पार्टी है जिसने राज्य में दो-भाषा नीति को लागू रखा और साफ कहा कि यहां हिंदी के लिए कोई जगह नहीं होगी। 'तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने में डीएमके की अहम भूमिका' उन्होंने यह भी दावा किया कि डीएमके ने ही राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा और तमिल भाषा को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान को तमिलनाडु की भाषा राजनीति और केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में लंबे समय से हिंदी विरोध और क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा काफी संवेदनशील रहा है।

## तिरुपति लहू घी मिलावट मामले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू का बयान, वाईएसआर कांग्रेस को घेरा

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वे तिरुपति लहू घी में कथित मिलावट के मामले में अगुवाई वाली एसआईटी ने पाया कि तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को संचालित करने वाली टीटीडी को घी के रूप में सप्लाई किया गया पदार्थ बिल्कुल भी शुद्ध घी नहीं था। इस मामले को पिछली वाईएसआर सरकार की खानदानी समस्या बताते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 और 2024 के बीच मिलावटी लहू परोसे गए। 2024 में दक्षिणी राज्य में एनडीए विधायक दल की मीटिंग के दौरान, नायडू ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकार ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर को भी नहीं बख्शा और लहू बनाने के लिए घटिया चीजों और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट जनरल को घी की जांच पूरी कर ली है। जानवरों की चर्बी के अलावा, नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआर सरकार के दौरान तिरुपति के लहूओं में बाथरूम साफ करने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल भी मिलाए गए थे।

## एआई समिट में हंगामा: सुधांशु त्रिवेदी ने यूथ कांग्रेस को बताया 'लश्कर-ए-राहुल', बोले- देश कभी माफ नहीं करेगा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 'लश्कर-ए-राहुल' के झंडाबरदार भारत की इज्जत को तार-तार करने में लगे हुए हैं। इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। 'कांग्रेस ने जो किया वह देश के साथ बगावत जैसा' सुधांशु त्रिवेदी ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, ये सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कहकर छोड़ा नहीं जा सकता।'

## एआई समिट में हंगामा: सुधांशु त्रिवेदी ने यूथ कांग्रेस को बताया 'लश्कर-ए-राहुल', बोले- देश कभी माफ नहीं करेगा

उन्होंने आगे कहा, 'ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष हैं, क्योंकि पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। इस तरह के राजनीति और राष्ट्र के विरोध की सीमा समाप्त होती है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के मन में शायद आज भी भारत की वह छवि है, जब भुखमरी थी और लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं थे। भारतीयों की अर्धनग्न तस्वीरें ही दिखाई जाती थीं। इसलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर वही पुराने भारत की अर्धनग्न तस्वीर दिखाने का प्रयास किया, जो निंदनीय है। यूथ कांग्रेस को बताया 'लश्कर ए राहुल' यूथ कांग्रेस को 'लश्कर-ए-राहुल' बताया है भाजपा प्रवक्ता ने कहा, 'अभी तक राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देते थे। अब 'लश्कर-ए-राहुल' के सिपाही भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।'

## ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः 'लाइफ फैक्टर आर्च' से लाइलाज बीमारियों का इलाज हुआ संभव

गाल ब्लॉक व किडनी में स्टोन की समस्या, रिक्त की समस्या आदि को बड़ी सहजता से 'लाइफ फैक्टर आर्च' के द्वारा ठीक किया जाता है। **अर्चना मिश्रा** मो: 7388351913 मधुबन से पीड़ित हनुमान देव से लोगों को भी पूरी तरह से ठीक करने का दावा

ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः 'लाइफ फैक्टर आर्च' से लाइलाज बीमारियों का इलाज हुआ संभव

आंव की रोगानी की समस्या, कान से ना सुनाई देने की समस्या, किडनी की समस्या, बुध की समस्या, गंजपन की समस्या

गाल ब्लॉक व किडनी में स्टोन की समस्या, रिक्त की समस्या आदि को बड़ी सहजता से 'लाइफ फैक्टर आर्च' के द्वारा ठीक किया जाता है।

**अर्चना मिश्रा**  
मो: 7388351913  
मधुबन से पीड़ित हनुमान देव से लोगों को भी पूरी तरह से ठीक करने का दावा

# बॉम्बे हाई कोर्ट की नौसेना को फटकार, ये कैसी खुफिया जानकारी? नाक के नीचे बन गई 20 मंजिला इमारत

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नौसेना की उस चुनौती पर सुनवाई करते हुए 'नौसेना खुफिया विभाग की विफलता' का जिक्र किया, जिसमें नौसेना ने कोलाबा में आईएनएस शिकरा के पास बन रही 20 मंजिला से अधिक ऊंची इमारत को चुनौती दी है। नौसेना इसे नौसैनिक प्रतिष्ठान के लिए संभावित खतरा मानती है। कोर्ट ने कहा कि अगर 2024 में शुरू हुआ यह निर्माण कार्य पहले ही उजागर होने के बजाय अब तक अनदेखा किया गया है, तो यह नौसेना की ओर से एक बड़ी चूक होगी।

न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और अभय मंत्री की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया, यह नौसेना की खुफिया जानकारी में स्पष्ट विफलता को दर्शाता है। पीठ ने डेवलपर को नौसेना के स्थानीय सैन्य प्राधिकरण द्वारा दायर याचिका की अंतिम सुनवाई तक किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण

न करने का निर्देश भी दिया। अदालत ने कहा कि जब ये टावरनुमा इमारतें 63 मीटर की ऊंचाई तक बनाई जा रही हैं, तो हमें आश्चर्य है कि



याचिकाकर्ता की खुफिया एजेंसी ने इमारत के डेवलपर के निर्माण पर ध्यान क्यों नहीं दिया, जिसने धीरे-धीरे एक के बाद एक मंजिलें बनाते हुए 2024 में ग्राउंड फ्लस 19 तक का निर्माण पूरा कर लिया।

पीठ ने डेवलपर और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को नौसेना को याचिका

का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, साथ ही इस बात पर चिंता व्यक्त की कि इमारत नौसेना की संपत्ति के सामने स्थित है। पीठ ने डेवलपर और बृहन्मुंबई

'यदि अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य हैं, तो हम उक्त मंजिलों को ध्वस्त करने का निर्देश देंगे। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नगर निगम या तो मिलीभगत कर रहा है या उसकी ओर से लापरवाही बरती गई है, या यदि परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि उसने याचिकाकर्ता की अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना अधिभोग प्रमाणपत्र या पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करके गलती की है।'

पीठ ने यह भी चेतावनी दी, 'यदि परिस्थितियां ऐसा संकेत देती हैं, तो हम नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन का निर्देश देने में संकोच नहीं करेंगे।'

पीठ ने निर्देश दिया कि डेवलपर 53 मीटर से ऊपर की मंजिलों के लिए फ्लैट नहीं बेचेगा या तृतीय-पक्ष अधिकार नहीं बनाएगा और खरीदारों को याचिका लंबित होने, अंतरिम आदेश और किसी भी प्रतिकूल परिणाम के जोखिम के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करेगा, जो ऐसे खरीदारों पर भी लागू होगा।

नगर निगम (बीएमसी) को नौसेना की याचिका का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, साथ ही इस बात पर चिंता के बाद एक मंजिलें बनाते हुए 2024 में ग्राउंड फ्लस 19 तक का निर्माण पूरा कर लिया।

पीठ ने डेवलपर और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को नौसेना को याचिका

का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, साथ ही इस बात पर चिंता व्यक्त की कि इमारत नौसेना की संपत्ति के सामने स्थित है। पीठ ने डेवलपर और बृहन्मुंबई

'यदि अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य हैं, तो हम उक्त मंजिलों को ध्वस्त करने का निर्देश देंगे। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नगर निगम या तो मिलीभगत कर रहा है या उसकी ओर से लापरवाही बरती गई है, या यदि परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि उसने याचिकाकर्ता की अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना अधिभोग प्रमाणपत्र या पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करके गलती की है।'

पीठ ने यह भी चेतावनी दी, 'यदि परिस्थितियां ऐसा संकेत देती हैं, तो हम नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन का निर्देश देने में संकोच नहीं करेंगे।'

पीठ ने निर्देश दिया कि डेवलपर 53 मीटर से ऊपर की मंजिलों के लिए फ्लैट नहीं बेचेगा या तृतीय-पक्ष अधिकार नहीं बनाएगा और खरीदारों को याचिका लंबित होने, अंतरिम आदेश और किसी भी प्रतिकूल परिणाम के जोखिम के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करेगा, जो ऐसे खरीदारों पर भी लागू होगा।

नगर निगम (बीएमसी) को नौसेना की याचिका का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, साथ ही इस बात पर चिंता के बाद एक मंजिलें बनाते हुए 2024 में ग्राउंड फ्लस 19 तक का निर्माण पूरा कर लिया।

पीठ ने डेवलपर और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को नौसेना को याचिका

# अजित पवार विमान हादसे पर रोहित पवार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, उड्डयन मंत्री को हटाने की मांग की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत का मामला अब सियासी तूफान बन गया है। एनसीपी-एसपी के विधायक रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नागरिक उड्डयन मंत्री के, राममोहन नायडू को पद से हटाने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। रोहित पवार ने कहा कि यह हादसा साधारण दुर्घटना नहीं हो सकता और इसकी गहराई से जांच जरूरी है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र की प्रति भेजी है।

रोहित पवार ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि 28 जनवरी की सुबह बरामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे के पीछे साजिश हो सकती है। इस हादसे में अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि यह पता लगाना जरूरी है कि मामला राजनीतिक साजिश है या व्यावसायिक साजिश। उनके

अनुसार, जिस एयर चार्टर कंपनी वीएसआर का विमान था, उसके खिलाफ कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

वीएसआर कंपनी और कथित लिंक पर सवाल रोहित पवार ने आरोप लगाया कि वीएसआर कंपनी और कुछ प्रभावशाली लोगों के बीच संबंधों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने पत्र में लिखा कि कंपनी और नागरिक उड्डयन मंत्री की पार्टी के बीच संभावित लिंक की



स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो। उनका कहना है कि उद्योग और राजनीति के कुछ ताकतवर लोग इस कंपनी के पीछे हैं, जिससे जांच पारदर्शी नहीं हो पा रही है। उन्होंने डीजेलीए की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की।

ब्लैक बॉक्स और विस्फोट पर संदेह रोहित पवार ने हादसे के ब्लैक बॉक्स को है या व्यावसायिक साजिश। उनके

दुर्घटना के समय एक नहीं, कई धमाके हुए थे। उनके मुताबिक, विमान में सामान रखने वाले हिस्से में अतिरिक्त पेट्रोल के कैन रखे गए थे, जिससे आग भड़की। उन्होंने कहा कि इन सभी पहलुओं की तकनीकी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से जांच होनी चाहिए।

मंत्री के इस्तीफे की मांग पत्र में रोहित पवार ने प्रधानमंत्री से अपील की कि अगर निष्पक्ष जांच करनी है तो पहले नागरिक उड्डयन मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने देश और महाराष्ट्र के लिए योगदान दिया है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनका दावा है कि जब तक शक्तिशाली लोगों की भूमिका की जांच नहीं होगी, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी।

इस हादसे को लेकर एनसीपी, शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस पहले ही सवाल उठा चुके हैं और 'फाउल प्ले' की आशंका जता चुके हैं। अब रोहित पवार के सीधे प्रधानमंत्री से दखल की मांग करने से मामला और गरमा गया है। आने वाले दिनों में इस पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों की प्रतिक्रिया अहम होगी। फिलहाल यह मामला सियासत और जांच दोनों के केंद्र में है।

# अतिक्रमण विभाग की ओर से कोपरखैरणे विभाग में निष्कासन कार्रवाई

दिव्यांश

नवी मुंबई महानगरपालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा जारी नोटिस के बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा नोटिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। माननीय आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे तथा अतिरिक्त आयुक्त (2) डॉ. राहुल गेथे के निर्देशानुसार

एक माननीय श्री कैलास गायकवाड, उपायुक्त (अतिक्रमण) वेड मार्गदर्शन में अतिक्रमण विभाग की ओर से कोपरखैरणे विभाग में निष्कासन की कार्रवाई की गई।

नवी मुंबई महानगरपालिका के कार्यक्षेत्र अंतर्गत कोपरखैरणे विभाग

में दिनांक 11/02/2026 को सेक्टर-07, कोपरखैरणे, नवी मुंबई स्थित ज्ञानेश्वर मौली ओनर्स एसोसिएशन के एक निवासी द्वारा शिकायत आवेदन प्राप्त

हुआ था। उक्त शिकायत के अनुसार जब अतिक्रमण विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, तो यह पाया गया कि सेक्टर-07, कोपरखैरणे में एस.एस. टाइप रूम क्रमांक 463 और एस.एस. टाइप रूम क्रमांक 465 के बीच स्थित खाली भूखंड पर शीट



पाइल डालकर 5.50 मीटर x 6.60 मीटर क्षेत्रफल का मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर था। इसवेग अनुसार सेक्टर-07,

कोपरखैरणे में एस.एस. टाइप रूम क्रमांक 463 और 465 के बीच स्थित खाली भूखंड में बने मंदिर की पीछे की दीवार एवं सामने की दीवार पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।

उक्त अनधिकृत निर्माण पर अतिक्रमण विभाग द्वारा ब्रेकर

अभियान के माध्यम से कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई वेड दौरान कोपरखैरणे विभाग के सहायक आयुक्त श्री भारत यू. धांडे, कनिष्ठ अभियंता श्री चंद्रकांत धोत्रे, अन्य अधिकारी/कर्मचारी तथा नवी मुंबई महानगरपालिका पुलिस बल उपस्थित थे। साथ ही

इस कार्रवाई के लिए 05 मजदूर, 01 इलेक्ट्रॉनिक हैमर एवं 01 गैस कट्टर का उपयोग किया गया।

आगे भी इस प्रकार के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उपयोग किया गया। आगे भी इस प्रकार के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

# पश्चिम रेलवे ने फिल्म शूटिंग से अर्जित की 1.72 करोड़ की रिकॉर्ड आय

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

यात्रियों और माल परिवहन से होने वाली आय को बढ़ाने के साथ-साथ पश्चिम रेलवे गैर-किराया राजस्व बढ़ाने के लिए कई नवाचारी पहल कर रहा है। इसी दिशा में पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2025-26 के दौरान फिल्म शूटिंग से आय अर्जित करने में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवधि में 15 फरवरी,

2026 तक पश्चिम रेलवे ने फिल्म शूटिंग से अब तक की सर्वाधिक लगभग 1.72 करोड़ की आय अर्जित की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25% अधिक है। इससे पहले वर्ष 2022-23 में पश्चिम रेलवे ने फिल्म शूटिंग से लगभग 1.64 करोड़ की आय अर्जित की थी। यह इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है

तथा अन्य रेलवे परिसरों को भी शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिससे फिल्म निर्माताओं को वास्तविक और जीवंत लोकेशन मिलती है।

पश्चिम रेलवे ने शूटिंग अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया है, जिससे प्रोडक्शन

हाउस और फिल्म निर्माताओं को निर्धारित समय में आवश्यक स्वीकृतियों तथा विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। समय-समय पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भी शूटिंग की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, याई तथा अन्य रेलवे परिसरों को भी शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिससे फिल्म निर्माताओं को वास्तविक और जीवंत लोकेशन मिलती है।

पश्चिम रेलवे ने शूटिंग अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया है, जिससे प्रोडक्शन



और रेलवे परिसरों को फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों, वेब सीरीज तथा विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। समय-समय पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भी शूटिंग की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, याई तथा अन्य रेलवे परिसरों को भी शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिससे फिल्म निर्माताओं को वास्तविक और जीवंत लोकेशन मिलती है।

पश्चिम रेलवे ने शूटिंग अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया है, जिससे प्रोडक्शन

हाउस और फिल्म निर्माताओं को निर्धारित समय में आवश्यक स्वीकृतियों तथा विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। समय-समय पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भी शूटिंग की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, याई तथा अन्य रेलवे परिसरों को भी शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिससे फिल्म निर्माताओं को वास्तविक और जीवंत लोकेशन मिलती है।

पश्चिम रेलवे ने शूटिंग अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया है, जिससे प्रोडक्शन

हाउस और फिल्म निर्माताओं को निर्धारित समय में आवश्यक स्वीकृतियों तथा विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। समय-समय पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भी शूटिंग की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, याई तथा अन्य रेलवे परिसरों को भी शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिससे फिल्म निर्माताओं को वास्तविक और जीवंत लोकेशन मिलती है।

पश्चिम रेलवे ने शूटिंग अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया है, जिससे प्रोडक्शन

# दुनिया में ईसाई, इस्लामिक, यहूदी और बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता: अनु कपूर

दिव्यांश

मुंबई। जाने माने अभिनेता अनु कपूर ने राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की बहस को केंद्र में ला खड़ा किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रगान से पहले 'वंदे मातरम्' के सभी छह श्लोक गाने के निर्देश का उन्होंने खुलकर स्वागत करते हुए इसे 'अद्भुत और ऐतिहासिक निर्णय' बताया है। अनु कपूर ने कहा कि यह राष्ट्र की चेतना के लिए शुभ संकेत है। अनु कपूर ने साथ ही वेद, उपनिषद्, रामायण और महाभारत को शांति, करुणा और विश्वकल्याण का संदेश देने वाला बताते हुए कहा कि भारतीय सभ्यता की आत्मा अहिंसा और सहअस्तित्व में विश्वास करती है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की कामना करने वाला समाज किसी के लिए खतरा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि अगर हिंदू प्रार्थना करता है तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समूचे विश्व के लिए मंगलकामना करता है। ऐसे में हिंदू पहचान से डर क्यों? उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू-मुस्लिम विभाजन की कथित खाई दरअसल राजनीतिक स्वार्थों की उपज है।

उन्होंने कहा कि जब दुनिया में ईसाई राष्ट्र हो सकते हैं, मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, यहूदी राष्ट्र हो सकते हैं, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो एक हिंदू



राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? अनु कपूर ने कहा कि समय आ गया है कि हिंदू एकता कायम हो और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाये। दूसरी ओर, अनु कपूर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल फिर उठने लगा है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए?

देखा जाये तो भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक जड़ें हिंदू सभ्यता में निहित हैं। यहां की परंपराएं, त्योहार, जीवन-दर्शन और सामाजिक



संरचना उसी धरोहर से निर्मित हुए हैं। हिंदू राष्ट्र का अर्थ किसी अन्य धर्म के प्रति घृणा नहीं, बल्कि उस मूल सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक स्वीकृति देना है, जिसने इस भूमि को आकार दिया। यह भी सत्य है कि 'धर्मनिरपेक्षता' की आड़ में अक्सर तुष्टिकरण की राजनीति

ने बहुसंख्यक समाज को अपराधबोध में जीने पर मजबूर किया है। यदि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है, तो इसका संदेश होगा कि यह राष्ट्र अपनी जड़ों पर गर्व करता है। यह वैसा ही होगा जैसे कई इस्लामी या ईसाई राष्ट्र अपनी धार्मिक पहचान के साथ भी लोकतांत्रिक ढांचा बनाए रखते हैं। इसके अलावा, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ कर सकती है। जब पहचान स्पष्ट होती है, तब भ्रम कम होता है। अनु कपूर का आह्वान इसी स्पष्टता की मांग करता है यानि धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाए, लेकिन अपनी मूल पहचान से समझौता किए बिना।

जहां तक हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आरएसएस के विचार की बात है तो हम आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत समय समय पर यह स्पष्ट करते रहे हैं कि भारत प्राचीन काल से ही हिंदू राष्ट्र है भले संविधान में इस प्रकार का कोई औपचारिक दर्जा ना हो लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र ही है।

आरएसएस के विचार की बात है तो हम आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत समय समय पर यह स्पष्ट करते रहे हैं कि भारत प्राचीन काल से ही हिंदू राष्ट्र है भले संविधान में इस प्रकार का कोई औपचारिक दर्जा ना हो लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र ही है।

# बार-बार बाथरूम जा रही थी छात्रा, शक होने पर खंगाला गया फोन, बोर्ड एजाम का पेपर ऐसे हुआ था लीक?

नागपुर। महाराष्ट्र बोर्ड एजाम में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दावा है कि 12वीं का केमिस्ट्री पेपर एजाम होने से पहले सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया।

यह मामला नागपुर का बताया जा रहा है। कथित तौर पर लीक हुए पेपर की अब पुलिस जांच कर रही है।

यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार (21 फरवरी) को दी है। बताया जा रहा है कि परीक्षा में कदाचार का यह मामला बुधवार को एक माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में सामने आया। एक छात्रा के बार-बार शौचालय जाने से संदेह पैदा हुआ और फिर इसका खुलासा हुआ। स्टूडेंट की वॉट्सएप चैट से खुला राज

अधिकारियों ने बताया कि परीक्षकों ने छात्रा का फोन जब किया और उसकी जांच करने पर पता चला कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही एक वॉट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन पेपर शेयर किया गया था। इस ग्रुप में संभावित उत्तरों को भी शेयर किया गया था। प्राइवेट कोचिंग से जुड़े शख्स पर आरोप अधिकारियों ने बताया कि छात्रा के

साझा किया था। इस संबंध में सदर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

11 फरवरी से चल रहे महाराष्ट्र



बयान के आधार पर एक अन्य छात्र से पूछताछ की जा रही है। मामले की प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलते हैं कि एक निजी कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसों के बदले प्रश्नपत्र

बयान के आधार पर एक अन्य छात्र से पूछताछ की जा रही है। मामले की प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलते हैं कि एक निजी कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसों के बदले प्रश्नपत्र

बयान के आधार पर एक अन्य छात्र से पूछताछ की जा रही है। मामले की प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलते हैं कि एक निजी कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसों के बदले प्रश्नपत्र



बयान के आधार पर एक अन्य छात्र से पूछताछ की जा रही है। मामले की प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलते हैं कि एक निजी कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसों के बदले प्रश्नपत्र

# किराए की कोख से अंगों की लूट तक, पैसों के लालच में महिलाओं को बनाया 'जिंदा लैब'

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में महिलाओं के घरों से गैर-कानूनी तरीके से उनके शूक्राणु बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस प्रकरण में बदलापुर पूर्व पुलिस स्टेशन में तीन महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी सुलक्षणा जयवंत गाडेकर अपने घर पर ही अवैध रूप से महिलाओं को शूक्राणु बढ़ाने वाले इंजेक्शन लगवाने का काम कर रही थी। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पैसों का लालच

देकर इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता था। जांच में सामने आया है कि बिना किसी चिकित्सकीय सलाह और कानूनी अनुमति के महिलाओं की सोनोग्राफी कराई जाती थी और उन्हें इंजेक्शन दिए जाते थे। इंजेक्शन के माध्यम से गर्भाशय में शूक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के बाद इन महिलाओं को आईवीएफ या सहायक प्रजनन तकनीक केंद्र भेजा जाता था।

आईवीएफ केंद्र में निकाल रहे थे शूक्राणु आरोप है कि संबंधित केंद्रों के डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में महिलाओं से प्रक्रिया के माध्यम से शूक्राणु निकाले। इसके बाद इन शूक्राणुओं को अवैध तरीके से बेचा गया। इस पूरे मामले में महिलाओं के शारीरिक और आर्थिक शोषण की गंभीर आशंका जताई जा रही है।



मोबाइल फोन में मिले चौकाने वाले सबूत बदलापुर उपजिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ज्योत्सना सावंत की टीम ने इस मामले का खुलासा किया। उनकी टीम ने सुलक्षणा गाडेकर के घर पर छाप मारा, जिसके बाद इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। इसके बाद उनकी शिकायत के आधार पर बदलापुर पूर्व पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच में आरोपी महिला के मोबाइल फोन से गर्भधारण के लिए उपयोग किए जाने वाले इंजेक्शन की

तस्वीरें, सोनोग्राफी की तस्वीरें, कुछ महिलाओं के फर्जी नामों से तैयार किए गए दस्तावेज़, शपथपत्र और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारियां मिली हैं। इससे इस रैकेट के और भी बड़े स्तर पर फैले होने की संभावना जताई जा रही है।

इस मामले में सुलक्षणा जयवंत गाडेकर के साथ आश्विनी चाबुकस्वा (जिला उल्हासनगर) और मंजूषा वानखेडे (जिला उल्हासनगर) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस के सामने आने के बाद बदलापुर क्षेत्र में चल रहे एक बड़े अवैध रैकेट के उजागर होने की संभावना है। बदलापुर पूर्व पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

**पश्चिम रेलवे**  
एलएचबी कार्य  
एसएमए/पीएल द्वारा निविदा क्रमांक: 52256840 आमंत्रित की जाती है।  
संक्षिप्त विवरण: एलएचबी कोचों के लिए कॉइल सिग्न फिल्टर बोगी का बोगी फ्रेम असेंबली कार्य। निविदा माला: 22 नं। कुल मूल्य: 66,19,800/- अंतिम तिथि: 25.03.2026 अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) पर जाएं।  
हमें फॉलो करें [facebook.com/WesternRly](https://www.facebook.com/WesternRly)

# 'माझी वसुंधरा' राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न

## 'माझी वसुंधरा' अभियान को जनआंदोलन बनना चाहिए- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश-इन पंचतत्त्वों का संरक्षण करना हमारी संस्कृति और कर्तव्य है। जलवायु परिवर्तन का संकट आज हमारे सामने खड़ा है। ऐसे समय में 'माझी वसुंधरा' अभियान के माध्यम से किए जा रहे वृक्षारोपण, ठोस कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण के कार्य अत्यंत सराहनीय हैं। 'माझी वसुंधरा' केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन बनना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने किया। उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा, 'जब हम पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात करते हैं, तो दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित दादा का स्मरण स्वाभाविक रूप से होता है। हमने प्रकृति के प्रति उनकी संवेदनशीलता कई बार देखी है। महाराष्ट्र ने अनेक क्षेत्रों में देश को दिशा दी है। दिवंगत

अजित दादा का यह स्वप्न था कि विकास केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित न रहे, बल्कि वह टिकाऊ हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और भावी पीढ़ियों का ध्यान रखने वाला हो।'

महाराष्ट्र एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि की निरभरता प्रकृति पर होती है। खेती भूमि, जल और वायु जैसे प्राकृतिक तत्वों पर आधारित है। इसलिए जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक दुष्प्रभाव कृषि पर पड़ता है। हम सभी को इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, वैज्ञानिक नियोजन और जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल महाराष्ट्र का निर्माण करने तथा भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, हरित और सक्षम महाराष्ट्र बनाने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार ने 'माझी वसुंधरा अभियान' में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी पुरस्कार-प्राप्त स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अभिनंदन किया।

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। पर्यावरण संरक्षण के लिए 'माझी वसुंधरा अभियान' के माध्यम से किया जा रहा कार्य अत्यंत सराहनीय है। 'माझी वसुंधरा अभियान' अब एक जनआंदोलन का रूप ले रहा है। यह भावी पीढ़ी के स्वस्थ जीवन के लिए जनसहभागिता से किया गया एक दिव्य कार्य है, ऐसा प्रतिपादन राज्यपाल आचार्य देवरत ने किया। रासायनिक खेती और पर्यावरणीय परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, यह बताते हुए उन्होंने इस अभियान को कृषि क्षेत्र से जोड़ने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वर्ली स्थित एएएससीआई डोम, सरदार वल्लभभाई पेटेल स्टेडियम में आयोजित 'माझी वसुंधरा' राज्यस्तरीय

पुरस्कार वितरण समारोह राज्यपाल आचार्य देवरत की उपस्थिति में संपन्न

राजेश अग्रवाल, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव जयश्री भोज,

राज्यस्तरीय पुरस्कारों का वितरण किया गया।

राज्यपाल श्री देवरत ने सरकार स्तर पर पहली बार पर्यावरण के लिए इतने बड़े और प्रभावी अभियान को लागू करने हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे का अभिनंदन किया। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण प्राकृतिक आपदाओं की आशंका वैश्विक स्तर पर व्यक्त की जा रही है। विश्व के जीवन के लिए प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि इस अभियान के माध्यम से किया जा रहा कार्य एक दिव्य सेवा है।

राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पांच सूत्र प्रस्तुत किए। विकास नीति के केंद्र में पर्यावरण संरक्षण को रखते हुए प्रत्येक विकास परियोजना में 'हरित ऑडिट' अनिवार्य किया जाना चाहिए।



हुआ। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावकर, मुख्य सचिव

राज्यपाल के सचिव प्रशांत नरनवरे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर 'माझी वसुंधरा मिशन 4.0 और 5.0' के अंतर्गत

# सतत विकास के माध्यम से सक्षम महाराष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

# क्या शरद पवार जा पाएंगे राज्यसभा? उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दिया दो टूक जवाब

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र का विकास पर्यावरण-अनुकूल तथा दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए नियोजित कार्यों, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और जनभागीदारी के माध्यम से सतत विकास द्वारा सक्षम महाराष्ट्र का निर्माण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसा प्रतिपादन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने किया। आज 'माझी वसुंधरा' अभियान के कारण पर्यावरण संरक्षण का विषय प्रत्यक्ष कार्यवाही के स्तर पर आ गया है। सरकार, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और नागरिकों के समन्वित प्रयास राज्य में स्थिरता के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। पर्यावरणीय शासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार 'माझी वसुंधरा' का राज्यव्यापी उपक्रम लागू कर रही है। अगले चरण में जैविक खेती अभियान लागू किया

जाएगा और श्रीमती मुंडे ने लोगों से उर्वर भूमि, स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु के लिए प्राकृतिक खेती अपनाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावकर ने कहा कि भारत 'वसुंधरा कुटुम्बक' के सिद्धांत

सौंपना हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है और प्रत्येक नागरिक को इस पर्यावरण प्रोत्साहन अभियान में जिम्मेदारीपूर्वक सहभाग लेना चाहिए, ऐसा आह्वान श्री नावकर ने किया। इस अवसर पर 'माझी वसुंधरा मिशन' पर आधारित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की गई। साथ ही मिशन की सफलता की कहानियों पर आधारित 'कॉफी टैबल बुक' और 'द क्लाइमेट चेंज लैक्सिकॉन' (मराठी-अंग्रेजी पर्यावरण शब्दकोश) का विमोचन मान्यवरों द्वारा किया गया।



में दृढ़ विश्वास रखता है। पर्यावरण संरक्षण इसी सिद्धांत का एक भाग है और इस अभियान को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से मिला प्रतिसाद निश्चित रूप से सराहनीय है। हमें अपने पूर्वजों से प्राकृतिक संपदा ऋण के रूप में प्राप्त हुई है। इसे अगली पीढ़ी को अच्छी स्थिति में

इस अवसर पर राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार - ग्राम पंचायत (कुल 18 स्थानीय स्वशासन संस्थाएं), राज्यस्तरीय द्वितीय, तृतीय, उच्च छलंग एवं प्रोत्साहन पुरस्कार (कुल 45), राज्यस्तरीय द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार (कुल 34 स्थानीय स्वशासन संस्थाएं), नगर परिषद तथा नगर पंचायत सुधारों को मान्यवरों, संस्थाओं और अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया।

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। महाराष्ट्र से राज्यसभा की एकमात्र संभावित सीट के लिए उम्मीदवार के चयन को लेकर महा विकास अघाड़ी में खींचतान चल रही है। इस बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि अगर शरद पवार चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो विपक्षी गठबंधन को इस पर चर्चा करनी होगी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) प्रमुख शरद पवार समेत सात सदस्य अग्रेल में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विपक्षी एमवीए सीटों में कमजोर सियासी गणित की वजह राज्यसभा में केवल एक उम्मीदवार भेज सकता है। पार्टी जिसका नाम देगी, उसे जिताने की कोशिश करेंगे : राउत नासिक जिले के मालेगांव में शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए संजय

राउत ने कहा, 'मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है और मैं पार्टी की नीति का पूरी तरह से पालन करता हूं। अगर

अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो हमें इस पर चर्चा करनी होगी। मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है। मैंने किसी



शरद पवार चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या होगा - यही एकमात्र सवाल हमारे सामने है। शिवसेना (यूबीटी) द्वारा जिसे भी उम्मीदवार नामित किया जाएगा, हम उसकी जीत के लिए प्रयास करेंगे। राउत ने कहा, 'अगर शरद पवार स्वयं

का नाम नहीं लिया है।' 14 फरवरी को राउत ने दावा किया था कि पवार राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और एमवीए इस बारे में चर्चा करेगी। महाराष्ट्र के किन नेताओं का खत्म हो रहा राज्यसभा में कार्यकाल? पवार के साथ-साथ शिवसेना (यूबीटी)

की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी (एसपी) की फौजिया खान, आरपीआई (अलावले) के रामदास अलावले, भाजपा के भगत कराड, कांग्रेस की रजनी पाटिल और एनसीपी के धैर्यशील पाटिल का राज्यसभा कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा।

आदित्य ठाकरे की उस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि एनसीपी के दोनों गुटों के एक साथ आने की स्थिति में जटिलताओं से बचने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी को एक और मौका दिया जाना चाहिए, राउत ने कहा कि ठाकरे एक वरिष्ठ नेता हैं और महाराष्ट्र को उनके बयान पर विचार करना चाहिए।

मालेगांव वेड उप महापाौर वेड कार्यालय में टीपू सुल्तान के चित्र के प्रदर्शन को लेकर उठे विवाद पर राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए 18वीं सदी के शासक का चित्र दादा रूप से इस्तेमाल कर रही है।

## भाजपा के मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन का तीखा हमला

# वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की कांग्रेस की सुनियोजित साजिश

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

'एआई समिट' में युवक कांग्रेस द्वारा किया गया प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने की एक सुनियोजित साजिश है-यह कड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन ने शनिवार को लगाया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में वे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एआई समिट में युवक कांग्रेस द्वारा कपड़े उतारकर किया गया प्रदर्शन अत्यंत शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा विश्वभर में गर्व के साथ ऊँची हो रही है। देश की प्रगति और बढ़ती शक्ति से असहज कांग्रेस ने इस प्रकार का निंदनीय कृत्य किया है-ऐसा भी श्री. बन ने कहा। इस अवसर पर श्री. बन ने बताया कि कांग्रेस के इस देश-विरोधी कृत्य के विरोध में कल भाजपुमो कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और आज भी राहुल गांधी के भिड़ंडी कोर्ट जाने समय भाजपुमो कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। देश-विरोधी एजेंडा चलाने वाली कांग्रेस को आने वाले समय में उसी

भाषा में जवाब दिया जाएगा-ऐसी चेतावनी भी उन्होंने दी। युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मतदाताओं द्वारा कांग्रेस को बार-बार नकारे जाने से उपजी बेचैनी के चलते राहुल गांधी देश में अस्थिरता और



अराजकता फैलाने का निरंतर प्रयास करते हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने यह लज्जाजनक बयान दिया था कि भारत की युवा पीढ़ी (जेन-जी) नेपाल जैसी अराजकता भारत में फैलाएगी। वर्तमान युवक कांग्रेस के आंदोलन के संदर्भ में इस बात की याद दिलाते हुए श्री. बन ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

साथ है-कांग्रेस कितने भी प्रयास कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जमानत पर बाहर नेता देश का नेतृत्व नहीं कर सकते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महात्मा गांधी की हत्या के बीच कोई संबंध न

होते हुए भी राहुल गांधी संघ पर निराधार आरोप लगाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता दी है और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी स्थिति स्पष्ट की थी, इसके बावजूद राहुल गांधी निराधार बयानबाजी कर रहे हैं-ऐसी आलोचना श्री. बन ने की। संघ और देश की बदनामी करना कांग्रेस का पसंदीदा उद्योग बन गया है। जमानत पर बाहर चल रहे नेता देश का नेतृत्व

नहीं कर सकते-यह तंज उन्होंने जमानत पर बाहर चल रहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हर्षवर्धन सपकाल पर कसा। संजय राउत को रोज नाक रगड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी

दादा भुसे पर कथित घोटाले के निराधार आरोप लगाने के मामले में संजय राउत के विरुद्ध मालेगांव कोर्ट में मानहानि का मुकदमा चल रहा है। इस प्रकरण में राउत को मालेगांव कोर्ट जाकर नाक रगड़नी पड़ेगी। बिना सबूत झूठे आरोप लगाने पर उन्हें न सिर्फ मालेगांव कोर्ट में, बल्कि रोज नाक रगड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी-ऐसी कटाक्षपूर्ण टिप्पणी उन्होंने की।

राज्यसभा चुनाव में भले ही उबाठा गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे हों, लेकिन संजय राउत की भूमिका निर्णायक होगी। आदित्य ठाकरे के मत की कोई अहमियत नहीं-यह भी इस बार सिद्ध होगा, ऐसा श्री. बन ने कहा। आदित्य ठाकरे को अपना एजेंडा और पसंद का नाम किनारे रखना पड़ेगा और राउत द्वारा आगे किए गए शरद पवार के नाम पर सहमति देनी पड़ेगी। राउत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे अगली बार कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे-यह लिखकर रख लीजिए, ऐसा तंज भी उन्होंने कसा।

# लव मैरिज करने की जिद कर रही थी 21 साल की बेटी, मां ने पाइप से गला दबा ले ली जान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के वावुज महानगर क्षेत्र में एक बेहद चौकाने वाली घटना सामने आई है। तिसगांव चौफुली इलाके में पुलिस को एक गढ़ में लिपटी हुई 20 साल की लड़की की लाश मिली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि लड़की की हत्या उसकी ही मां ने प्रेम संबंध के विरोध में गला घोटकर की थी।

मृतका की पहचान नंदिनी राजु धिवरे के रूप में हुई है। 35 साल की आरोपी मां भारती उमेश साबले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 19 फरवरी की रात डायल 112 टीम को एक रिक्शा चालक से सूचना मिली कि तिसगांव

चौफुली पुल के पास एक रिक्शा में संदिग्ध तरीके से गद्दा और धरेलू सामान ले जाया जा रहा है। गढ़ में लिपटी लाश, सबूत मिटाने की कोशिश सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक महिला और एक



व्यक्ति रिक्शा के साथ मौजूद थे, उनके पास एक प्लास्टिक ड्रम और रस्सी से बंधा हुआ गद्दा था। पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने गद्दा खोला, जिसमें एक लड़की का शव बराबद

हुआ। शुरुआत में मां ने दावा किया कि लड़की ने आत्महत्या की है और वे शव को गांव ले जा रहे थे, लेकिन गढ़ में लिपटी लाश, सबूत मिटाने का कि लड़की की मौत गला घोटने से हुई थी। प्रेम संबंध बना हत्या की वजह

जांच में सामने आया कि नंदिनी का एक कपड़े युवक से प्रेम संबंध था और वह उससे शादी करने की जिद कर रही थी। इस बात को लेकर मां और बेटे के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद के चलते मां ने प्लास्टिक पाइप से नंदिनी का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी, इसके बाद शव को गढ़ में लपेटकर तिसगांव चौफुली पुल के पास ले जाकर फेंकने की कोशिश की गई, ताकि सबूत मिटाए जा सकें। रिक्शा चालक ने बताया कि वडगांव कोल्हाटी से तिसगांव चौफुली तक सामान ले जाते समय उसे गढ़ में कुछ संदिग्ध लगा, जब सामान उतारा जा रहा था, तब उसने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की त्वरित कार्यवाही से पूरा मामला उजागर हो गया। पुलिस ने आरोपी मां भारती उमेश साबले के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।

# गहनों के लिए पोते ने 72 साल की दादी का किया मर्डर, चाय में जहर मिलाकर पिलाया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गंगावेश इलाके में ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के पास स्थित शुक्रतारा अपार्टमेंट में रहने वाली 72 साल की उषा मारुति भिड़ंडे की उनके ही रिश्तेदार ने गहनों की लालच में चाय में जहर मिलाकर हत्या कर दी। इस वारदात के सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है।

लोकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए मृतका के पोते प्रेम परशराम भिड़ंडे (उम्र 20, निवासी चिंतामणि पार्क, फुलेवाड़ी रिंग रोड, कोल्हापुर) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

ऐशो-आराम के लिए गहनों की चाह में किया जाल में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे अपनी ऐशो-आराम की जिंदगी के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी लालच में उसने अपनी दादी के सोने के

गहने चुराने की योजना बनाई और उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, उषा भिड़ंडे अपने पोते के साथ रहती थीं, लेकिन कुछ दिन पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वह घर में अकेली रह रही थीं। परिवार का ही एक सदस्य परशराम उनकी दवाइयों और अन्य जरूरतों में मदद करता था। सोमवार को उषा अचानक घर में बेहोश हो गईं, उस समय परशराम ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि उषा की

मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। तकनीकी जांच में खुला राज पुलिस ने मृतका की रोजमर्रा की आदतों,



उनकी दवाइयों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर जांच शुरू की। जांच में

यह सामने आया कि मौत वाले दिन यानी सोमवार सुबह प्रेम भिड़ंडे उनके घर आया था।

तकनीकी और गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने प्रेम को उसके घर से हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसने जानबूझकर चाय में जहरीला केमिकल मिलाया था, जिसे उषा ने पी लिया। चाय पीते ही वह बेहोश हो गईं और कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। मौत की पुष्टि के बाद उतारे गहने आरोपी ने बताया कि उषा की मौत की पुष्टि करने के बाद उसने उनके दोनों

हाथों से छह सोने के कंगन, गले से दो सोने की चेन और दाहिने कान का सोने का फूल उतार लिया। इसके बाद उसने यह दिखाने की कोशिश की कि उषा की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। हालांकि, पुलिस जांच में पूरा मामला सामने आ गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

## सम्पादकीय

## एआइ बदलेगा विकास का भविष्य, दिल्ली समिट से उभरीं संभावनाएं और चुनौतियां

यह एक जगजाहिर तथ्य है कि दुनिया आज तकनीकी विकास के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका एक सबसे अहम औजार बनने जा रही है। दिल्ली में आयोजित 'इंडिया-एआइ इम्पैक्ट समिट, 2026' में इस संदर्भ में जितने आयाम सामने आए, वे बताते हैं कि दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ केंद्रित बदलाव अब विकास की नई परिभाषा गढ़ने जा रहा है। इसमें भारत की एक अहम भूमिका होगी और खासतौर पर वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों में इसे नेतृत्वकारी भूमिका में देखा जा रहा है।

गौरतलब है कि एआइ का इस्तेमाल अब केवल सुरक्षा के मुद्दे तक केंद्रित नहीं है और आज विकास के क्षेत्र में समावेशी, पारदर्शी तथा जिम्मेदार सुशासन के तौर पर इसकी भूमिका का विस्तार हो रहा है। जहां तक दिल्ली में हुए एआइ सम्मेलन का सवाल है, इसमें स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शासन और आर्थिक विकास के मामले में खड़ी होने वाली बाधाओं का हल निकालने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को आगे बढ़ाने की जमीन तैयार करने की कोशिश की गई। यानी सम्मेलन में एआइ के जरिए समग्र विकास के क्षेत्र में संभावनाओं की नई राह तलाशने की भूमिका बनी।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान तकनीक, चिकित्सा और अन्य उत्पादों के निर्माण तथा उपयोग में एआइ का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। विकास के लगभग सभी क्षेत्र में इसकी अहमियत जिस रूप में बनती देखी जा रही है, उसके मद्देनजर भारत ने भी अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन यह भी सच है कि फिलहाल इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका की कंपनियों का वर्चस्व है।

निश्चित तौर पर भारत जैसे विकासशील देशों के सामने यह एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी समस्या से पार तभी पाया जा सकता है, जब उसकी जटिलता को स्वीकार कर उसका सामना करने का विकल्प चुन लिया जाए। इस लिहाज से देखा जाए, तो भारत का यह रुख तकनीकी प्रतिस्पर्धा के मैदान में चुनौतियों का सामना करने की जमीन तैयार करता है कि देश एआइ से डरता नहीं है, बल्कि इसमें वैश्विक भलाई के लिए समृद्धि और भविष्य की संभावनाएं देखता है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि एआइ अब भविष्य की दुनिया का एक यथार्थ है और विकास की पटकथा तैयार करने में इसकी अहम भूमिका होने जा रही है। मगर इसके समांतर यह देखने की जरूरत होगी कि नए बनने वाले ढांचे में समाज के सभी वर्गों के हित को सुनिश्चित करने का उद्देश्य किस हद तक पूरा हो पाता है। इस संदर्भ में एआइ की बढ़ती भूमिका के दौर में बड़े पैमाने पर नौकरियों का दायरा सिकुड़ने और अवसर कम होने की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसका हल निकालना एक बड़ी चुनौती होगी।

इसके अलावा, एआइ आधारित तकनीक का बेजा इस्तेमाल करके भयादोहन, डीपफेक से जुड़ी जटिलताएं, डेटा केंद्रों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव, ज्यादा से ज्यादा डेटा हासिल करके उसका मनमाना उपयोग और उसे नियंत्रण का एक औजार बनाने जैसे सवाल भी सामने खड़े होंगे। इन समस्याओं का हल निकालने पर ही इस तकनीक की साख निर्भर करेगी।

यों दिल्ली के सम्मेलन में एक सकारात्मक उम्मीद यह जताई गई कि एआइ अरबों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकता है और एक बेहतर दुनिया बना सकता है। मगर यह इस पर निर्भर करेगा कि एआइ की नई दुनिया में वंचित तबकों एवं गरीब आबादी की कितनी पहुंच संभव हो सकेगी और इसका चेहरा कितना मानवीय तथा समावेशी बनाया जा सकेगा।



## लक्ष्य से दूर कार्बन उत्सर्जन पर लगाम, भारत की अपनी चिंताएं और चुनौतियां

धरती का तापमान न बढ़े, इसके लिए कवायद तो हो रही है, लेकिन दुनिया भर के देशों की वर्तमान नीतियां ऐसी हैं जो तापमान को 2.3 से 2.5 डिग्री तक ले जा सकती हैं। हालांकि कई देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया है। फिर भी 29 देशों में कार्बन उत्सर्जन उच्च स्तर पर बना हुआ है। दूसरी ओर, भारत कम उत्सर्जन के साथ मध्यम प्रदर्शन कर रहा है।

'कार्बन मार्केट वाच' की रपट बताती है कि वर्तमान समय में विश्व के कई बड़े देश जलवायु परिवर्तन रोकने में सफल नहीं रहे हैं। लिहाजा 1.5 डिग्री तापमान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 43 फीसद कमी लाने की जरूरत है। मगर इसकी उम्मीद अभी नहीं दिख रही है। कई बड़े उद्योगों का कामकाज जलवायु लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है। सच यह है कि वैश्विक तापमान बढ़ने से रोकने के प्रयास अपर्याप्त हैं।

पिछले जी-20 सम्मेलन में शामिल देशों में वर्ष 2050 तक पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी को डेढ़ डिग्री तक रखने पर सहमति बनी थी। यह अच्छी बात है कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देता है। मगर यह भी सच है कि भारत के विकास लक्ष्यों के

साथ जलवायु अनुकूलन का तालमेल स्थापित करने में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में भारत ने कई महानों तक गर्म हवाओं, बाढ़ और चक्रवात जैसी विषम मौसमी घटनाओं का सामना किया था, जिससे जन-जीवन से लेकर लोगों की आजीविका तक प्रभावित हुई। साथ ही विकास कार्यों के लिए यह स्थिति बाधा बनी रही।

'नेट जीरो' का मतलब ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य करना भर नहीं है, बल्कि इन गैसों को दूसरे कामों से संतुलित करना भी है। ऐसी अर्थव्यवस्था भी तैयार करना है, जिसमें जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल न के बराबर हो। साथ ही कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी कम से कम हो। अभी जितना कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, उसी के अनुपात में उसे अवशोषित करने का भी इंतजाम हो।

यह पर्यावरण संरक्षण से ही संभव है। यदि कार्बन उत्सर्जन एक निश्चित मात्रा में होता है और उत्सर्जन करने वाली इकाई उसी अनुपात में पेड़ों को महत्व देती है, तो कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण की समानता के कारण उत्सर्जन को शून्य स्तर पर ले जाना आसान

## राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के वर्षपर्यंत सियासी मायने

चिरजीवी सदन 'राज्यसभा' के द्विवार्षिक चुनाव के लिए वर्ष 2026 में विभिन्न चरणों में खाली होने वाली कुल 71-75 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जो पूरे वर्ष अप्रैल और नवंबर में भरी जाएंगी। लिहाजा, इन चुनावों के राजनीतिक मायने गहन व अहम हैं, क्योंकि ये चुनाव जहां एनडीए की बहुमत मजबूती बढ़ा सकते हैं, वहीं विपक्ष को भी कमजोर कर सकते हैं। इससे भाजपा व उसके साथियों का चुनावी हौसला बढ़ेगा।

जहां तक इनकी प्रमुख तारीखों की बात है तो चुनाव आयोग ने पहले चरण में 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव घोषित किए हैं। जिसके लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी, नामांकन 5 मार्च तक, और मतदान-मतगणना 16 मार्च 2026 को। जबकि बाकी सीटें नवंबर में भरी जाएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन दस चुनावी राज्यों में से 6 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जबकि 4 राज्यों में इंडी गठबंधन के घटक दल सरकार में हैं। जहां तक राज्यवार सीटों की बात है कि पहले चरण में महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, बिहार की 5, ओडिशा की 4, असम की 3, हरियाणा की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीटें शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में उत्तरप्रदेश की 10 और झारखंड, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना आदि की 20 से अधिक सीटों के लिए नवम्बर में चुनाव होंगे।

जहां तक उच्च सदन राज्यसभा में वर्तमान दलगत स्थिति की बात है तो राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जहां भाजपा के 103 और एनडीए के 121-129 सांसद हैं। जबकि विपक्षी इंडिया

क्लॉक के पास 78-80 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के 27 सांसद हैं। जहां तक इन चुनावों के राजनीतिक प्रभाव की बात है तो इन चुनावों में एनडीए को 7-9 या इससे अधिक सीटों का लाभ मिलने का अनुमान है, जिससे उनकी संख्या 145 तक पहुंच सकती है। जबकि विपक्ष को 5 सीटें खोने का खतरा,



खासकर बिहार, महाराष्ट्र में है। इससे भाजपा को राज्यसभा में अब कोई भी विधेयक पास करना आसान होगा और सुपरमेजॉरिटी की ओर बढ़त भी उसे मिलेगी।

सवाल है कि इन चुनावों में एनडीए को कितनी सीटें मिलने की संभावना है तो राजनीतिक विश्लेषकों को अनुमान है कि एनडीए को 2026 के राज्यसभा चुनावों में कुल 48 या इससे अधिक सीटें मिलने की संभावना है, जिससे उनकी ताकत 129 से बढ़कर 140ए हो सकती है। पहले चरण के 37 सीटों पर 5-7 का लाभ अनुमानित है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बाद के चरणों से भी उसे अतिरिक्त मजबूती मिलेगी।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, 71-75 खाली सीटों में से एनडीए को नेट 7-9 या 48 सीटें हासिल हो सकती हैं। चूंकि वर्तमान में एनडीए के 121-129 सदस्य हैं, इसलिए चुनाव बाद 145 तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं बाद के जून-नवम्बर वाले दूसरे चरणों के प्रभाव की बात है तो वे भी स्पष्ट हैं। उत्तर प्रदेश

क्लॉक वर्तमान 80 सीटों से 75 पर सिमट सकता है। कांग्रेस को विशेष रूप से 8 सीटें खोने का खतरा, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे, दिग्विजय सिंह की सीटें भी शामिल हैं। वहीं बाद के चरणों का प्रभाव भी उमपर पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटें में से सपा को 2-3 मिलनी संभावित है, लेकिन कुल

नुकसान होगा। जबकि कर्नाटक, झारखंड में 1-1 सीटों का नुकसान संभव है। ओवरऑल, एनडीए के लाभ से इंडिया कमजोर होगा।

जहां तक राज्यवार स्थिति की बात है तो बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होगा। अभी आरजेड के 2, जेडीयू के 2 और एक सांसद राष्ट्रीय लोक मोर्चा का है। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के पास 202 विधायक हैं और एनडीए के खाने में 4 सीटें सुनिश्चित हैं, जबकि 5 के लिए जोर आजमाइश बढ़ेगी। क्योंकि यहां 35 सीटों के साथ I.N.D.I.A.

एक भी सीट अपने बल पर जीतने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में 5 विधायकों वाला AIMIM की भूमिका अहम हो जाती है। यदि पूरा विपक्ष एकजुट होता है तो बिहार में विपक्ष के पास कुल 41 विधायक हो जाते हैं और विपक्ष एक सीट निकाल सकते हैं। ऐसे में यह चुनाव तेजसी यादव के नेतृत्व और विपक्षी एकता की के लिए अग्निपरीक्षा होगा। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व में सत्तारूढ़ महायुति आसानी से 6 सीटों पर जीत हासिल कर लेगा, वहीं 7वीं सीट के लिए वोटिंग हो सकती है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीतिक के चाणक्य कह जाने वाले शरद पवार का संसदीय सफर थम सकता है। जबकि हरियाणा से बीजेपी के दो सदस्य किरण चौधरी और रामचंद्र जांगरा का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इसी प्रकार ओडिशा की 4 सीटों पर चुनाव होगा, जहां अभी 2 सीट बीजेपी और 2 बीजेडी के पास हैं लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी की सीटों में इजाफा होना तय है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में दोनों सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं और यहां भी बीजेपी जीत दर्ज करने की स्थिति में है।

रही बात तेलंगाना की तो वहां से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी रिटायर हो रहे हैं और बीआरएस के एक कैंडिडेट का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस दोनों सीटें जीत सकती है और हिमाचल में भी कांग्रेस एक सीट जीत सकती है। असम से तीन पश्चिम बंगाल से 5 और तमिलनाडु से भी 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। चूंकि इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इन राज्यों में

आर रिश्ते भी। यही कारण है कि अब दूटने रिश्ते किसी को ज्यादा विचलित नहीं करते। सोशल मीडिया पर 'ब्लॉक' और 'अनफ्रेंड' रिश्तों को खत्म करने का सबसे आसान रास्ता बन गए हैं। जहां पहले रिश्ते निभाने के लिए समझौते और त्याग की जरूरत होती थी, वहां अब एक क्लिक से रिश्ता खत्म करना आम हो गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने भी रिश्तों की आत्मा को गहराई से प्रभावित किया है। पहले रिश्ते अपनापन और जिम्मेदारी के आधार पर चलते थे। अब वे लाभ-हानि के तराजू में तौले जाने लगे हैं। दोस्ती तब तक है, जब तक काम आ रही है। विवाह तब तक है, जब तक सुख और सुविधा मिल रही है। पड़ोस तब तक है, जब तक उससे कोई फायदा जुड़ा हुआ है। यह मानसिकता रिश्तों को खोखला कर रही है। रिश्ते अब जिम्मेदारी कम और सौदेबाजी ज्यादा लगने लगे हैं।

त्योहारों की दुनिया में भी यही बदलाव दिखता है। पहले दीपावली पर घर-घर जाकर मिठाइयां बांटी जाती थीं, अब आनलाइन तोहफे

का 'वाउचर' भेजना काफी समझा जाता है। होली पर गले मिलने की जगह 'हैपी होली' का संदेश भेज देना सामान्य हो गया है। ईद की सेवई और क्रिसमस का केक अब 'वाट्सएप स्टिकर' तक सिमट गया है। त्योहारों की आत्मा रिश्तों की गहराई थी, जो अब बाजार और तकनीकी की चमक में कहीं खोती जा रही है।

फिर भी तस्वीर पूरी तरह अंधेरी नहीं है। बदलते रिश्तों के इस मौसम ने नई संभावनाएं भी खोली हैं। अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों की स्वीकृति बढ़ रही है। दूरदराज के रिश्तेदार मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए लगातार जुड़े रह सकते हैं। मगर मूल सवाल वही है कि क्या यह सब रिश्तों को जीवित रखने के लिए काफी है? क्या आभासी अपनापन वास्तविक संवेदना की जगह ले सकता है? सच तो यही है कि रिश्ते निभाने के लिए तकनीक से अधिक संवेदना चाहिए। उन्हें जीवित रखने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर वह मानवीय स्पर्श चाहिए,

सत्तारूढ़ पार्टियों के पास राज्यसभा में अपना संख्याबल कायम रखने का मौका मिलेगा।

यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग से निपटने की चुनौती विपक्ष के सामने रहेगी। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती हमेशा होती है। पिछले कुछ राज्यसभा चुनावों को देखें तो हरियाणा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। इसलिए आने वाले राज्यसभा चुनावों को देखें तो चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, यहां पर कांग्रेस और सहयोगी दलों को फूंक-फूंक करकदम रखना होगा। हालांकि कुछ सीटों पर तो रिजल्ट पहले से ही तय है, लेकिन अगर विपक्ष क्रॉस वोटिंग को रोक पाता है तो उसके हाथ भी कुछ सीट आ सकती हैं। चूंकि राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस वर्ष 75 सीटों पर होने वाले चुनावों में विपक्ष यदि कारगर रणनीति नहीं बनाता है तो फिर इंडिया गठबंधन वाले कांग्रेस और उसके सहयोगियों की संख्या और घट सकती है, इतना तय है। जहां तक इन चुनावों में प्रमुख नेताओं के प्रभावित होने की बात है तो कई दिग्गजों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के शरद पवार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जदयू नेता हरिवंश, भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी (6 मंत्री सहित) शामिल हैं। वहीं बीएसपी राज्यसभा से साफ हो सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 7, सपा को 2 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं राजद और बीजद समेत कई दलों की सीटें घटेगी।

## आत्मा खोने पर सिर्फ नाम और नंबर की सूची बनकर रह जाएंगे रिश्ते

रिश्ते कभी वसंत की तरह खिलखिलते हैं, कभी बरसात की तरह गीला-गीला होते हैं, कभी ग्रीष्म की तरह तपते हैं और कभी पतझड़ की तरह सूने-सूने लगते हैं। मगर बीते कुछ दशकों में इनका बदलना सिर्फ स्वाभाविक चक्र नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीव के गहरे बदलावों का आईना भी बन गया है। आज जब हम चारों ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि रिश्तों का रूप, उनकी परिभाषा और उनका निभाया जाना-सब कुछ बदल रहा है। यह स्थिति हमें कभी सूझते देती है, तो कभी बेचैनी से भर देती है।

कभी भारतीय समाज की सबसे बड़ी पहचान संयुक्त परिवार हुआ करती थी। एक ही छत के नीचे तीन-चार पीढ़ियों साथ रहती थीं। बच्चों का पालन-पोषण सिर्फ मां-बाप तक सीमित नहीं था, उसमें दादी-नानी का दुलार, बड़ों की डांट और छोटे-बड़े भाई-बहनों की शरारतें शामिल थीं। त्योहार धार्मिक अवसर मात्र नहीं होते थे, बल्कि वे पारिवारिक एकजुटता और रिश्तों की मजबूती का उत्सव होते थे। अब वही संयुक्त परिवार टूटकर छोटे-

छोटे फ्लैटों में सिमट गए हैं। महानगरों की नौकरी और पढ़ाई ने हमें ऐसी जगह पहुंचा दिया है, जहां न तो आंगन हैं, न चौपाल। चार पीढ़ियों का साथ अब दुर्लभ हो गया है। रिश्तों की नजदीकी धीरे-धीरे दूरी में बदल गई है।

डिजिटल क्रांति ने इस दूरी को और भी गहराई दी है। दोस्त अब मोहल्ले की गली या गांव की चौपाल पर नहीं मिलते, वे सोशल मीडिया और आभासी खेलों की दुनिया में मिलते हैं। भाई-बहन एक ही घर में रहकर भी अपने-अपने डिजिटल कमरों में कैद हैं। किसी के कानों में हेडफोन हैं, किसी की आंखों पर मोबाइल की स्क्रीन चमक रही है। माता-पिता के पास बच्चों से बात करने का समय नहीं और बच्चों के पास माता-पिता को सुनने का धैर्य नहीं। संवाद जो काम भी रिश्तों की जान हुआ करता था, अब सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर 'स्टेटस अपडेट' की दुनिया में बिखर गया है। शिकायतें सीधे कहे जाने के बजाय इशारों और 'इमोजी' में बदल गई हैं।

यह भी सच है कि डिजिटल

दुनिया ने कुछ नए रास्ते खोले हैं। परदेस गया बेटा अब अपनी मां से रोज वीडियो काल के जरिए बात कर सकता है। बहन-भाई रखाबंधन पर आनलाइन तोहफे भेज सकते हैं। विदेश में बैठा छात्र अपने गांव की शादी का सीधा प्रसारण देख सकता है। यह सब तकनीक की देन है और रिश्तों को नई तरह की निकटता भी देती है। मगर सवाल यही है कि क्या यह निकटता असली अपनापन बन पाती है? दिल का 'इमोजी' क्या संयुक्त धड़कते दिल की गर्माहट पहुंचा सकता है? एक वीडियो काल क्या मां की गोद का विकल्प हो सकता है?

नई पीढ़ी रिश्तों को बराबरी की नजर से देखती है। बेटियां अपने फैंसले खुद ले रही हैं, बेटे घर के कामों में हाथ बंटा रहे हैं। विवाह और दोस्ती, दोनों में बराबरी का भाव बढ़ा है। जाति और धर्म के बंधनों को भी धीरे-धीरे चुनौती दी जा रही है। यह बदलाव सकारात्मक है, क्योंकि यह रिश्तों को न्यायपूर्ण और अधिक मानवीय बना रहा है। मगर साथ ही यह पीढ़ी धैर्य और प्रतीक्षा से भी दूर जा रही है। हर चीज उन्हें तुरंत चाहिए-खाना, प्यार

और रिश्ते भी। यही कारण है कि अब दूटने रिश्ते किसी को ज्यादा विचलित नहीं करते। सोशल मीडिया पर 'ब्लॉक' और 'अनफ्रेंड' रिश्तों को खत्म करने का सबसे आसान रास्ता बन गए हैं। जहां पहले रिश्ते निभाने के लिए समझौते और त्याग की जरूरत होती थी, वहां अब एक क्लिक से रिश्ता खत्म करना आम हो गया है।

उपभोक्तावादी संस्कृति ने भी रिश्तों की आत्मा को गहराई से प्रभावित किया है। पहले रिश्ते अपनापन और जिम्मेदारी के आधार पर चलते थे। अब वे लाभ-हानि के तराजू में तौले जाने लगे हैं। दोस्ती तब तक है, जब तक काम आ रही है। विवाह तब तक है, जब तक सुख और सुविधा मिल रही है। पड़ोस तब तक है, जब तक उससे कोई फायदा जुड़ा हुआ है। यह मानसिकता रिश्तों को खोखला कर रही है। रिश्ते अब जिम्मेदारी कम और सौदेबाजी ज्यादा लगने लगे हैं।

त्योहारों की दुनिया में भी यही बदलाव दिखता है। पहले दीपावली पर घर-घर जाकर मिठाइयां बांटी जाती थीं, अब आनलाइन तोहफे

जैसे कोई मशीन नहीं दे सकती। रिश्तों का मौसम चाहे जैसे भी बदले, उनकी आत्मा वही पुरानी है- विश्वास, अपनापन और जिम्मेदारी। अगर आत्मा बची रही तो रिश्ते बदलते मौसमों में भी हरे-भरे रहेंगे। अगर यह आत्मा खो गई, तो रिश्ते सिर्फ नामों और नंबरों की सूची बनकर रह जाएंगे। आज हमें यही तय करना है कि हम किस मौसम में जीना चाहते हैं- वसंत की गुनगुनाती चरमाहट में या पतझड़ की सूनी उदासी में।

हाल ही में तमिलनाडु के शिवांगंगा जिले के करांडिकुडी में अपनी जड़ों से जुड़े रहने की एक घटना चर्चा में आई। यहां एक ही परिवार की पीढ़ियों ने गांव-घर लौटने का मन बनाया। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जा बसे इन लोगों ने व्यस्तता और जीवन की आपाधापी को भूल कर एक-दूजे से मिलने का मार्ग निकाला और अपने पैंतूक आवास पर पहुंच गए। बिखरते रिश्तों के इस दौर में विश्वास पीढ़ियों को जोड़ने की एक प्रेरणादायी घटना है।

नतीजा अब पूरी दुनिया देख रही है। अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह होता रहा, तो वर्ष 2050 तक पृथ्वी का तापमान दो डिग्री बढ़ जाएगा। यह पूरी दुनिया के लिए भयावह होगा। लोगों को भीषण सूखा से लेकर निराशाकारी बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। हिमखंड और अधिक पिघलेंगे। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। ऐसे में कई देशों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा होगा। दुनिया के 192 देश संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हिस्सा हैं। इनमें 137 देश शून्य उत्सर्जन का समर्थन करते हैं। देखा जाए, तो कुल

ग्रीनहाउस उत्सर्जन में इनकी हिस्सेदारी 80 फीसद है। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले चीन और अमेरिका भी इसी में शामिल हैं। चीन ने वर्ष 2026 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस मामले में वह कितना खरा उतरेगा, कहना मुश्किल है। दूसरी ओर, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश 2045 तक, जबकि आस्ट्रिया, फिनलैंड और उरुग्वे ने अलग-अलग समय में शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।

अमेरिका के अलावा ऐसे कई देश हैं जो इस मामले में कहीं आगे जाकर वर्ष 2050 तक शून्य

उत्सर्जन का लक्ष्य रखते हैं। इस बीच सुखद यह है कि जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती के बीच भारत के वन क्षेत्र में वर्ष 2021 के दौरान तीन फीसद से अधिक बढ़ोतरी हुई। वैसे भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर दूसरे देशों के मुकामले कहीं अधिक चिंतित है। इस समय वह नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (काप-26) में भारत ने इस मामले में अपना पक्ष रखा था। अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा को किसी भी तरह कम किया जाए। दूसरा यह कि अपनी 50 फीसद ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा से कैसे पूरा किया जाए। वहीं कार्बन उत्सर्जन को भी कम करते जाना है।

इसके अलावा, वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य तो है ही। हालांकि समय की कसौटी पर कौन कितना खरा उतरेगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है, यह अब पूरी दुनिया में दिखने लगा है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में हरित विकास पर जोर दिया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनाना और

वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। बजट में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी बड़ी राशि आबंटित की गई है और ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तथा परमाणु ऊर्जा के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ष के बजट में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने की पहल दिखती है। हरित ऊर्जा गलियारा, परमाणु ऊर्जा पर जोर और हरित बुनियादी ढांचा- ये सब ऐसे संदर्भ हैं, जिन पर भारत 'पृथ्वी प्रथम' की नीति को महत्व देता है। जबकि कुछ ताकतवर देश अपनी नीतियों में 'देश प्रथम' को महत्त्व दे रहे हैं। नतीजा यह कि इसकी कीमत शेष देश चुका रहे हैं।

दुनिया भर के देश अगर किसी भी तरह जल्दी अथवा धीरे-धीरे ही सही कार्बन उत्सर्जन कम करने की सही पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। यह निराशाजनक ही है कि कार्बन उत्सर्जन पर लगाम के मुद्दे पर दुनिया के देशों में कागजी एकजुटता तो देखने को मिलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वे सार्थक पहल करते नहीं दिखते। वहीं विकसित और विकासशील देशों के बीच नाहक ही इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप चलता रहता है। सभी को

सोचना होगा कि भौगोलिक सीमाओं में बेशक सभी देश बंटे हुए हैं, लेकिन धरती तो एक ही है और सभी को मिल कर उसे बचाना है। दुनिया को यह सोचना पड़ेगा कि 'राष्ट्र प्रथम' की नीति लेकर नहीं, बल्कि वैश्विक सुशासन के साथ काम करना होगा। फिलहाल भारत की अपनी चिंताएं और चुनौतियां हैं। अगर यह का बन उत्सर्जन पर सख्ती से कदम उठाता है, तो इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। सच भी है कि अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत कार्बन उत्सर्जन के मामले में संयमित देश है और यह अपने संकल्प को पूरा करने की कोशिश करता है।

पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में राज्य वृक्ष 'खेजड़ी' को काटे जाने और गांवों की चरागाह भूमि के अधिग्रहण का व्यापक स्तर पर विरोध होना कोई सामान्य घटना नहीं है। स्थानीय लोगों की ओर से इन दरख्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पारंपरिक चरागाहों के संरक्षण को मांग ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि जिस सौर ऊर्जा को पर्यावरण हितैषी माना जाता है, क्या उसी के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना उचित है?



सीआरपीएफ कर्मी के खाते से 30 हजार रुपये उड़ाए

# महाप्रबंधक द्वारा वंदे भारत प्रोटोटाइप रिक का निरीक्षण; प्रारंभिक ट्रायल सफलतापूर्वक सम्पन्न

मंत्र भारत संवाददाता रायबरेली। प्रशान्त कुमार मिश्रा, महाप्रबंधक, एमसीएफ ने कारखाना परिसर में वंदे भारत प्रोटोटाइप रिक का निरीक्षण किया। यह वंदे भारत परियोजना की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

निरीक्षण के दौरान कारखाना परिसर में प्रथम चरण के गति परीक्षण सम्पन्न किए गए। इस अवसर पर एमसीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, मेसर्स सीमेन्स के प्रतिनिधि तथा अन्य उद्योग सहयोगी उपस्थित रहे। ड्राइवर केबिन से प्रमुख ऑनबोर्ड प्रणालियों का परीक्षण किया गया।

सीमेन्स की टीम द्वारा पैंटोग्राफ-वीसीबी (वैक्यूम सर्किट ब्रेकर) संचालन तथा उच्च वोल्टेज आदि का निरीक्षण किया गया। ये सभी क्रियाएं ड्राइवर डेस्क यूनिट से सफलतापूर्वक संचालित की गईं, जिससे प्रणाली की समन्वित कार्यक्षमता एवं परिचालन तत्परता

शेड से प्रारंभिक संचालन के दौरान रिक की गति को 10 किमी/घंटा की सीमित निर्धारित गति पर



प्रदर्शित हुई। एक लघु ट्रायल रन भी किया गया, जिसमें ट्रैक्शन, गति तथा ओवरड्राइव इतिवृत्तों से लिए गए कंट्रोल जैसे प्रमुख परीक्षण मानकों का अवलोकन किया गया। ट्रायल

रिक का विस्तृत निरीक्षण भी किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का सत्यापन शामिल था। महाप्रबंधक महोदय ने प्रकाश व्यवस्था के समुचित एलाइनमेंट तथा विद्युत व्युत्पत्ति की वैक्यूम एवं मैग्नेटिक क्लीनिंग के माध्यम से गहन सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी धात्विक अवशेष को हटाकर उच्चतम सुरक्षा एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

यह उपलब्धि एमसीएफ एवं उसके उद्योग सहयोगियों के बीच सुदृढ़ समन्वय एवं सहयोग का प्रतीक है, जो वंदे भारत परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रशांत कुमार मिश्रा ने इस अवसर पर विवेक खरे, प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता; विजय, मुख्य विद्युत डिजाइन अभियंता;

अनुराग दत्त त्रिपाठी, सीडब्ल्यू/फर्निशिंग; मेसर्स सीमेन्स के अनुराग गुप्ता; तथा आरडीएसओ के अनुपम गुप्ता और विष्णु शंकर प्रसाद सहित सभी उद्योग सहयोगियों को उनके समर्पण, समन्वय एवं उत्कृष्ट टीमवर्क के लिए बधाई एवं धन्यवाद दिया।

दिनांक 12 फरवरी 2026 को आयोजित ट्रायल पूर्व निरीक्षण के दौरान मेसर्स सीमेन्स के जर्मन अभियंता - क्रिस्टोफ गोएटज़, सुसैज़ा स्पॉसेट एवं सेबास्टियन शोएसर, पदमाकर डीके, सैत कर- भी उपस्थित रहे तथा तकनीकी कार्यवाही में सक्रिय सहभागिता की। यह ट्रायल एमसीएफ की अत्याधुनिक, उच्च गति वाली ट्रेनसेट के निर्माण हेतु उसकी प्रतिबद्धता, नवाचार क्षमता एवं उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को पुनः स्थापित करता है।

## श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन बारह अवतारों का हुआ वर्णन

मंत्र भारत संवाददाता थरवई। सात दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। कथावाचक पूज्य कृपाशंकर महाराज जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान विष्णु के बारह अवतारों की कथा का विस्तार से वर्णन किया। उनके प्रवचनों से पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। कथावाचक ने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह सहित अन्य अवतारों के माध्यम से धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अवतार मानव जीवन को सत्य, धर्म और कर्णों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कथा का आयोजन सहजोपुर गांव निवासी शारदा प्रसाद द्विवेदी पत्नी सुषमा देवी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं।



## मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को किया जागरूक

मंत्र भारत संवाददाता सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी बांसी रोहिणी यादव तथा थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा थाना खेसरहा के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम नए निरीक्षक जियाउल्लाह,

महिला कांस्टेबल अंजली यादव द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत थाना क्षेत्र के ग्राम लोहपुरवा में दहेज उत्पीड़न व 03 नये कानून के बारे में महिला सशक्तिकरण संबंधी बातों को बताते हुए बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत सरकार के विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व बहु सम्मेलन अभियान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष नारी शक्ति वंदन अधिनियम मातृ शक्ति को सम्बल निराश्रित महिला पेंशन योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानकारी दी गयी तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई।

मिशन शक्ति फेज 5.0 के विषय में महिलाओं को महिला सम्वन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 बुमने पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108एमएलएस हेल्प लाइन, 101अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एडवर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर नए कानून के बारे में जानकारी दी गई।

## बारात में शामिल होने गए युवक की अज्ञात वाहन की ठोकर से हुई मौत

मंत्र भारत संवाददाता सिद्धार्थनगर। जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के रोमनदेई गांव में शुक्रवार की रात एक दर्दनाक इलाक़ हदसे में 17 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक बारात में शामिल होने गया था तभी अज्ञात चार पहिया वाहन ने उसे ठोकर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

मिली जानकारी के अनुसार शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के रमापुर तिवारी निवासी शनि निषाद पुत्र मुकेश निषाद उम्र 17 वर्ष शुक्रवार रात रोमनदेई गांव में आयोजित एक बारात समारोह में शामिल होने गया था। बताया जा रहा है कि रात करीब 10:30 बजे वह सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ़्तार अज्ञात चार पहिया वाहन ने उसे जोरदार ठोकर मार दी और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल शनि को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल शोहरतगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गये जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की असमय मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है वहीं पूरे गांव में शोक व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलते ही शोहरतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। इस संबंध में शोहरतगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है तथा अज्ञात वाहन की पहचान के लिए टीम को लगा दी गई है।



## पुलिस ने महिला सुरक्षा के प्रति स्कूली छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

मंत्र भारत संवाददाता सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद व प्रवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रामदेव थाना गोल्हेरा के निर्देशन में थाना क्षेत्र के कम्पोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय बरायदा में बालिकाओं को उप निरीक्षक दीनदयाल सिंह, हेड कांस्टेबल शीला पटेल जागरूक किया गया तथा बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत सरकार के विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व बहु सम्मेलन अभियान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना रानी

लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष नारी शक्ति वंदन अधिनियम मातृ शक्ति को सम्बल निराश्रित महिला पेंशन योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानकारी दी गयी तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में तथा हेल्पलाइन नं० 1090 बुमने पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एडवर हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम हेल्प लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।



## डीएम की अध्यक्षता में सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन 41 प्रार्थना पत्र में से 6 का हुआ निस्तारण

मंत्र भारत संवाददाता सिद्धार्थनगर। जिले में शासन के मंशा के अनुरूप आज तहसील नौगढ़ में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन की उपस्थिति में सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। तहसील नौगढ़ में आयोजित सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस के आयोजन के अवसर पर राजस्व, विकास, शिक्षा, पूर्ति एवं अन्य विभागों के शिकायतों की सुनवाई जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, उपजिलाधिकारी नौगढ़ कल्याण सिंह मौर्य द्वारा तथा पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन द्वारा किया गया।

जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा तहसील समाधान दिवस में पिछले समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के आख्या का अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भूमि से संबंधित विवाद मौके पर जाकर निरीक्षण कर निस्तारण कराये। जिलाधिकारी

शिवशरणप्पा जीएन ने सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस नौगढ़ में उपस्थित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसील समाधान दिवस में प्राप्त कानूनी मौके पर जाकर शिकायत के निस्तारण से पूर्व निरीक्षण कर उसके बाद की आख्या लायेंगे इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तहसील में जन्म/



हो रही शिकायतों एवं आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समय से एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही शिकायतकर्ता एवं विपक्षी दोनों के समक्ष जांच कर कार्यवाही किया जाये। किसी भी विभाग का तहसील दिवस का कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं होना चाहिए यदि किसी भी विभाग का प्रकरण लम्बित पाया जायेगा तो सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। लेखपाल एवं

मृत्यु प्रमाण-पत्र रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जिसमें जन्म प्रमाण-2500 तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र 1000 जारी करने के प्रकरण लम्बित पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उपजिलाधिकारी नौगढ़ को प्रतिकूल प्रतिक्रिया दी गयी। साथ ही वेतावनी दिया गया कि 15 दिवस में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण न होने की दशा में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी। सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस के आयोजन के अवसर

पर कुल 41 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए जिसमें राजस्व-30, पुलिस विभाग से सम्बन्धित-04, नगर पालिका-01, विकास-01, मनरेगा-02, स्वास्थ्य-01, बाल विकास-02 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए। जिलाधिकारी द्वारा राजस्व के 06 प्रार्थना-पत्रों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। तहसील दिवस में प्राप्त शेष शिकायतों प्रार्थना पत्रों को तीन दिवस के अन्दर शत-प्रतिशत निस्तारण की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस कार्यक्रम के इस अवसर पर उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा रजत कुमार चौरसिया, पीडी नानोन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, डीडीओ राजमणि वर्मा, डीसी मनरेगा सन्दीप सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झा, जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, तहसीलदार नौगढ़, तहसील नौगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त थानाध्यक्ष एवं खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

## मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह स्थल की व्यवस्था का डीएम, एसएसपी व पूर्व मंत्री ने किया निरीक्षण

मंत्र भारत संवाददाता सिद्धार्थनगर। जिले के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा पूर्व मंत्री व विधायक बांसी जय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन के साथ रतन सेन महाविद्यालय बांसी में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रतनसेन महाविद्यालय में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यातायात व्यवस्था, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण, महिला सुरक्षा, वीआईपी आगमन-प्रस्थान मार्ग तथा आपातकालीन निकास व्यवस्था कराये जाने के बारे में सम्बन्धित को निर्देश दिया। इसके अलावा वर-बधू को दी जाने वाले सामानों की सूची का बैनर लगवाने का निर्देश दिया। पीने के पानी व अन्य आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक डा ज्ञानप्रकाश, उपजिलाधिकारी बांसी निखिल चक्रवर्ती, पीडी नानोन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी महिपाल सिंह व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्र भारत संवाददाता सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन ने प्रशान्त कुमार प्रसाद के कुशल निर्देशन में, सुबेन्द्र सिंह किशोर पुलिस इकाई के नोडल अधिकारी/क्षेत्राधिकारी अपराधा के कुशल पर्यवेक्षण में, मनोज कुमार श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा एवं समन्वय गोष्ठी की गयी। जिसमें पूर्व में जारी किए गए कार्यवृत्त का अनुपालन के संबंध में चर्चा की गई। उपस्थित अन्य अधिकारी गण द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी एसओपी अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/विवेकों के समक्ष आ रही



## आगामी त्यौहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक

मंत्र भारत संवाददाता सिद्धार्थनगर। जिले के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकृपाल संपन्न कराने के लिए थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी विवेकानंद मिश्रा व क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रहरियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ विस्तृत वार्ता कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी होली का पर्व परंपरागत तरीके से ही मनाया जाएगा तथा किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट

अपील की।सीओ ने होली के अवसर पर अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, भंडारण एवं सेवन पर सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने आश्चर्य किया कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रहरियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बीते वर्ष होली के दिन बाणगंगा बैराज पर हुई दुर्घटना का भी उल्लेख किया गया। प्रशासन ने इस वर्ष एहतियातन होली के दिन बैराज के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में नदी में स्नान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही बैराज पर प्रकाश व्यवस्था, एनाउंसमेंट और पुलिस बल की नैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। होली पर्व को सकृपाल संपन्न कराने

हेतु प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। बैठक में चेयरमैन प्रतिनिधि रवि अग्रवाल, सुधांशु बोरा, सूर्य प्रकाश पाण्डेय, शिव प्रसाद वर्मा, सौरभ गुप्ता, शैलेन्द्र कौशल, मनोज कुमार गुप्ता, महेश कसौधन, दिलीप वर्मा, वीरेंद्र मोहनवाल, संजय दुबे, निसार अहमद, रोहित मड्डेशिया, अल्ताफ हुसैन, वकील खान, वीरेंद्र प्रताप जायसवाल, रमेश मणि त्रिपाठी, संतोष पासवान, विवेक पाण्डेय, अजय चौधरी, सुभाष यादव, मेजर सिंह चौहान, पिंटू सिंह, बबलू गौड़, प्रमोद श्रीवास्तव, वीरेंद्र गौड़, राजू बाबा, शौकी लाल, राम मिलन चौधरी, ओमप्रकाश यादव, पिंटू पटेल सहित एसडीओ विद्युत विनोद कुमार, लिपिक राजेश त्रिपाठी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।



## बाल श्रम और मानव तस्करी के रोकथाम के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक गोष्ठी का आयोजन

मंत्र भारत संवाददाता सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन के आदेश के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद के कुशल निर्देशन में, सुबेन्द्र सिंह किशोर पुलिस इकाई के नोडल अधिकारी/क्षेत्राधिकारी अपराधा के कुशल पर्यवेक्षण में, मनोज कुमार श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा एवं समन्वय गोष्ठी की गयी। जिसमें पूर्व में जारी किए गए कार्यवृत्त का अनुपालन के संबंध में चर्चा की गई। उपस्थित अन्य अधिकारी गण द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी एसओपी अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/विवेकों के समक्ष आ रही

समस्या, एवं सुझाव पीड़ितों के आवासन, बाल गुम्हड़ा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन पोस्को को एक्ट के अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पोस्को के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरकर संबंधित को समय से भेजा जाना बाल कल्याण

अधिकारी के कर्तव्य का पालन, जे.जे.एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारियों रिमांड लेने हेतु साढ़े दसों में आने जे.जे.एक्ट की धारा 24 आदि तथा पोस्को एक्ट से संबंधित अभियुक्तों की माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त बेल नोटिस को अंदर समय अल्पव्य करना के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान जनपद सिद्धार्थनगर के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, जनपद के समस्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारीगण, एएचटीयू/एसजेपीयू के अधिकारी/कर्मचारीगण, मानव सेवा संस्थान गोरखपुर एनजीओ के कर्मचारीगण, मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान सिद्धार्थनगर के अधिकारी/कर्मचारीगण गण शामिल हुए।



# भिवंडी अदालत में पेश हुए राहुल गांधी

आर एस एस से जुड़े 2014 के बयान पर दर्ज केस में नए जमानतदार के लिए हुए उपस्थित



भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मानहानि मामले में सुनवाई के सिलसिले में भिवंडी की अदालत में पेश हुए। इस मामले में पहले जमानतदार रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर के निधन के बाद नए जमानतदार की आवश्यकता के कारण उन्हें अदालत में उपस्थित होना पड़ा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की है।

अदालत में सुनवाई न्यायाधीश पी. एम. कोलसे की अदालत में हुई, जहां मामले के शिकायतकर्ता राजेश कुंटे भी उपस्थित रहे। राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने जमानतदार के रूप में बॉण्ड प्रस्तुत किया। अधिवक्ता नारायण अय्यर ने बताया कि जमानत बॉण्ड पर हस्ताक्षर और अन्य न्यायिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राहुल गांधी वापस लौट गए। राहुल गांधी के अदालत पहुंचने की खबर के बाद कांग्रेस पदाधिकारी और नव-निर्वाचित नगरसेवक उनसे मिलने के लिए अदालत परिसर में मौजूद थे, लेकिन वे किसी से मुलाकात किए

4 अप्रैल को मानहानि मामले की अगली सुनवाई शहर में रही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

बिना ही वहां से रवाना हो गए। निर्धारित समय से लगभग 15 मिनट पहले अदालत पहुंचकर उन्होंने न्यायालय के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। राहुल गांधी के आगमन को देखते हुए शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शिकायतकर्ता राजेश कुंटे ने कहा कि भारतीय कानून के अनुसार जमानत प्रक्रिया आवश्यक थी और अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि न्याय व्यवस्था

से ऊपर कुछ भी नहीं है। यह मामला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा है। भिवंडी तालुका के सोनाले गांव में आयोजित एक सभा में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका होने का आरोप लगाया था। इसके विरोध में संघ पदाधिकारी राजेश कुंटे ने अदालत में मानहानि की निजी शिकायत दर्ज कराई थी।

इस बीच मुंबई के मुलुंड टोल नाका क्षेत्र में राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाए जाने की घटना पर कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया। कई कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि इस तरह की घटना सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर है और सरकार तथा पुलिस प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बात्या मामा ने कहा कि 2014 में दर्ज मानहानि का मामला 12 वर्ष बाद भी लंबित है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि इस मामले को सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में कर जल्द निर्णय किया जाए।

## भिवंडी से दो नाबालिग फिर लापता, अपहरण की आशंका से दहशत

अलग-अलग इलाकों से लड़की व किशोर गायब। पुलिस ने दर्ज किए अपहरण के केस

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी और आसपास के इलाकों में नाबालिग बच्चों के लापता होने की घटनाएं धमने का नाम नहीं ले रही हैं।

शिकायत दर्ज कराई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी घटना भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सोमानगर इलाके की है, जहां 14 वर्षीय किशोर अहमद के



एक बार फिर अलग-अलग क्षेत्रों से एक नाबालिग लड़की और एक किशोर के लापता होने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली घटना शांतिनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है, जहां 17 वर्ष 10 माह की एक नाबालिग लड़की 18 फरवरी की शाम करीब 8 बजे से लापता है। लड़की के पिता, जो पावरलूम मजदूर है, ने

लापता होने का मामला सामने आया है। धामणकर नाका स्थित चॉल निवासी जुमन फिर मोहम्मद अंसारी (48) दोपहर करीब 2 बजे घर पहुंचे तो उनका बेटा घर पर नहीं मिला। आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। भोईवाड़ा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू कर दी है। दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है।

## भिवंडी में महिला व नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप, एक गिरफ्तार पांच पर केस दर्ज

बाइक विवाद में महिला से अभद्रता का मामला दर्ज, छात्रा से कथित छेड़छाड़ में आरोपी हिरासत में भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी में महिला और एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। पुलिस ने दोनों घटनाओं में शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

के अनुसार वाराला देवी तालाब क्षेत्र की एक 10 वर्षीय छात्रा पैदल घर लौट रही थी, तभी आरोपी प्रवेश केदारनाथ उपाध्याय (50) ने कथित रूप से उसका पीछा कर रास्ते में रोक लिया और हाथ पकड़ लिया। परिजनों की

शिकायत पर भिवंडी शहर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मामलों की आगे जांच जारी है।

## हाईवे पर ट्रक की टक्कर, बाइक सवार दंपति घायल...

तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, पति का पैर फ्रैक्चर, पत्नी भी जख्मी। भिवंडी। मुंबई-नाशिक हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा 20 फरवरी की दोपहर करीब 3:30 बजे खारेगांव ब्रिज के पास हुआ। पुलिस के अनुसार दिनेश मुनींद्र कोंडाबतीनी (30) अपनी पत्नी मोनिका के साथ मोटरसाइकिल से ठाणे से भिवंडी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आए ट्रक ने लापरवाही से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दिनेश के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया तथा हाथ में भी चोट आई है, जबकि उनकी पत्नी के हाथ और पैर में चोट आई है। घायल की शिकायत पर नारपोली पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



## भिवंडी में कांग्रेस बैनरों से शहर अध्यक्ष की फोटो गायब सपा विधायक की बड़ी तस्वीरों से सियासी चर्चा तेज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी में हाल ही में लगे कांग्रेस के बधाई बैनर-पोस्टरों को लेकर स्थानीय राजनीति गरमा गई है। बैनरों से कांग्रेस शहर अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर की फोटो गायब होने और उनकी जगह समाजवादी पार्टी के विधायक रईस कासम शेख की बड़ी तस्वीरें लगाए जाने से सियासी हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर में महापौर और उपमहापौर के निर्वाचन के बाद लगाए गए बधाई बैनरों में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस शहर अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर की फोटो अधिकांश बैनरों से नदारद बताई जा रही है। उनके स्थान पर भिवंडी सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बात्या मामा और समाजवादी पार्टी विधायक रईस कासम शेख की तस्वीरें प्रमुखता से लगाई गई हैं। कांग्रेस कार्यलय के बाहर लगा बैनर भी लोगों के बीच चर्चा का

विषय बना हुआ है। स्थानीय राजनीतिक हलकों में इसे लेकर अटकलों का दौर जारी है। कुछ लोग इसे कांग्रेस संगठन के भीतर बदलते समीकरणों से जोड़कर

चुनाव में कांग्रेस 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे पार्षदों की बताई जाती है जिन्हें समाजवादी पार्टी विधायक के

घटनाओं को भी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा गया था। महापौर चुनाव में भी दिलचस्प राजनीतिक समीकरण देखने को मिले। कांग्रेस और राष्ट्रवादी



देख रहे हैं, जबकि कई लोग यह भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक का प्रभाव कांग्रेस के स्थानीय संगठन पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस संबंध में कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि भिवंडी महानगरपालिका

कांग्रेस पार्टी के समर्थन से भाजपा के बागी उम्मीदवार नारायण चौधरी को महापौर चुना गया। बताया जाता है कि विभिन्न दलों और गुटों के समर्थन से उन्हें कुल 48 मत प्राप्त हुए थे। इसके बाद उपमहापौर पद पर कांग्रेस के तारिक अब्दुल बारी निर्वाचित हुए थे। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले कुछ जनप्रतिनिधि और सक्रिय कांग्रेस के कुछ नेता भी विधायक रईस कासम शेख के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस बैनरों से शहर

अध्यक्ष की तस्वीरें गायब होने को लेकर संगठन के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा जारी है। राजनीतिक जानकार इसे भिवंडी की स्थानीय राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत मान रहे हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से किसी भी दल की ओर से इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है।

## 7 लाख 39 हजार के आभूषण व बाइक बरामद, चोरी के 6 मामलों का हुआ पर्दाफाश

## भिवंडी क्राइम ब्रांच पुलिस ने लूटपाट व वाहन चोरी गिरोह के दो आरोपी को दबोचा

बंद घरों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को बनाते थे निशाना, वाहनों को भी करते थे पार भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी क्राइम ब्रांच पुलिस ने सोना और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह के दो शांतिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से पुलिस ने करीब 7 लाख 39 हजार रुपये कीमत के सोने के आभूषण और चोरी में इस्तेमाल किए गए वाहन बरामद किए हैं। इस आरोपियों के पकड़े जाने से चोरी के छह मामलों का पर्दाफाश हो गया है। भिवंडी क्राइम ब्रांच के सीनियर पीआई शीतल राउत ने बताया कि ठाणे पुलिस आयुक्त ने बढ़ती चोरी पर अंकुश लगाने का सख्त निर्देश दिया। जिसके तहत क्राइम ब्रांच पुलिस ने गुप्त सूचना व तांत्रिक विश्लेषण के आधार पर जाल बिछाया आभूषण व वाहनों की चोरी करने वाले एक गिरोह

के दो आरोपियों को शुक्रवार को सूरत से गिरफ्तार किया है। जिनका नाम

सूरत के दिडोली के रहने वाले है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों



आजाद सिंह उर्फ धनारी माधुसिंह टाक (33) व अजय सिंह उर्फ मामू भूरासिंह (28) हैं। जो गुजरात राज्य के

ने 6 चोरी को अंजाम देने वाले वारदातों में अपनी संलिप्तता कबूल की है। जिसमें नारपोली पुलिस स्टेशन हद में 4, कोन

गांव में एक विरार पुलिस स्टेशन हद में अंजाम दिए चोरी के वारदात शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी से सोना चोरी और वाहन चोरी के कई लंबित मामलों के सुलझने की संभावना है। सीनियर पीआई शीतल राउत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से शहर और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। वे गिरोह बंद घरों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को निशाना बनाकर सोने के आभूषणों की चोरी करता था, वहीं मोका मिलते ही दोपहिया और चारपहिया वाहन भी पार कर देता था। गिरफ्तार आरोपियों के पास करीब 7.39 लाख रुपये के चोरी के आभूषण व वाहन बरामद किया गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और मामले की आगे जांच की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की संभावना बढ़ गई है।

## भिवंडी मनपा के पूर्व महापौर को आखिरकर कोर्ट ने दी जमानत, समर्थकों में खुशी

धोखाधड़ी के मामले में 13 फरवरी को ठाणे आर्थिक अपराध शाखा ने किया था गिरफ्तार

भिवंडी। भिवंडी मनपा के पूर्व महापौर विलास पाटिल की जमानत को आखिरकार अदालत ने मंजूर कर दिया है। जिन्हें ठाणे आर्थिक अपराध शाखा ने चीटिंग के मामले में 13 फरवरी को मनपा महापौर चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार किया था। हालांकि अदालत ने उन्हें 20 फरवरी को हुए महापौर चुनाव में मतदान करने तथा 16 फरवरी को नामांकन के लिए कड़ी पुलिस सुरक्षा में मनपा मुख्यालय में जाने की अनुमति प्रदान किया था।



हिरासत में भेज दिया था। पूर्व महापौर विलास पाटिल के वकील एडवोकेट नारायण अय्यर ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में उनकी जमानत मंजूर कर ली है। इससे पहले मनपा चुनाव में जीत के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर हुए विवाद के मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में विलास पाटिल को 7 फरवरी को उन्हें अग्रिम जमानत मिली थी।

जानकारी के मुताबिक, ठाणे आर्थिक अपराध शाखा ने 13 फरवरी की देर रात आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में विलास पाटिल को हिरासत में लिया था। जिन्हें विशेष सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले चार दिनों तक यानी 18 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद कोर्ट ने 18 फरवरी को ऑनलाइन माध्यम से हुई सुनवाई में उन्हें पुनः 21 फरवरी तक न्यायिक

## सुप्रीम कोर्ट से टैरिफ रद्द होते ही अचानक चीन के लिए निकले ट्रंप, क्या बड़ा खेल कर रहा अमेरिका?

वांशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टैरिफ नीति को गैरकानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस फैसले के तुरंत बाद एक और बड़ी खबर सामने आती है कि ट्रंप अब चीन दौरे पर जाने वाले हैं और वहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनिपिंग से होने वाली है। हालांकि इस फैसले से तीन जज वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। 20 फरवरी 2026 को अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह फैसला 63 के बहुमत से दिया गया है और इसने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति पर सीधा ब्रेक लगा दिया।

फैसले में साफ कह दिया कि इस कानून में कहीं भी टैरिफ लगाने की शक्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यानी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के इतने बड़े पैमाने पर आया शुल्क नहीं लगा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति असीमित मात्रा, अवधि और दायरे में टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा कर रहे थे। लेकिन इसके लिए कांग्रेस की अनुमति जरूरी है। हालांकि इस फैसले से तीन जज असहमत भी दिखे। लेकिन बहुमत का फैसला लागू हो गया और ट्रंप की टैरिफ नीति पर कानूनी रोक लगा दी गई।

## डोनाल्ड ट्रंप के हर कदम का कर रहे अध्ययन, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले के बाद भारत सरकार सतर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारतीय सरकार अमेरिकी टैरिफ और उनके प्रभावों से संबंधित घटनाक्रमों का अध्ययन कर रही है। यह प्रतिक्रिया शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद आई है। 6-3 के विभाजित फैसले में, अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया कि ट्रंप कांग्रेस की

मंजूरी के बिना 1974 के आईईपीए कानून के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमने कल (शुक्रवार) अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले पर ध्यान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मंत्रालय ने आगे कहा कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं

और हम इन सभी घटनाक्रमों के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र इस फैसले की जांच करेगा

और वाणिज्य मंत्रालय या विदेश मंत्रालय को इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देगे। जोशी ने कहा कि मैंने मीडिया में पढ़ा है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ फैसला सुनाया है और भारतीय सरकार उसका अध्ययन करेगी। जो भी प्रतिक्रिया देनी होगी, वह वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाएगी, कि न मेरे द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर

कर कुछ टैरिफ संबंधी कार्रवाइयों को समाप्त कर दिया और एक अस्थायी आयात अधिभार लगाने की घोषणा की। यह अस्थायी 10 प्रतिशत आयात शुल्क 24 फरवरी को पूर्ण मानक समय के अनुसार रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा। कुछ टैरिफ हटाने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर कर अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत अस्थायी आयात अधिभार को 'मूल्य-आधारित शुल्क' के रूप में लागू किया।







# महाप्रबंधक ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया

# आयुर्वेद की वैश्विक पहचान के अग्रदूत हैं डॉ. जी. एस. तोमर



## नई दिल्ली (संवाददाता)

### मंत्र न्यूज

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार पांडे ने त्योंहार के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेने के लिए आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने अजमेरी गेट की तरफ वाले प्रवेश द्वार, एस्केलेटर, फुट ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया।

उन्होंने भीड़भाड़ प्रबंधन का भी मूल्यांकन किया तथा स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं पर यात्रियों की प्रतिक्रिया लेते हुए उनके साथ बातचीत की। उन्होंने प्लेटफार्म नं. 16 पर मिनी कंट्रोल रूम का दौरा किया तथा आगामी होली त्यौहार के दौरान यात्रियों की आवाजाही के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ श्री प्रवेश रमन त्रिपाठी, मंडल रेल प्रबंधक, दिल्ली; श्री प्रवीण पांडे, पीसीसीएम, उत्तर रेलवे; श्री पंकज गंगवार, पीसीएससी/

आरपीएफ; श्री प्रेम शंकर गुप्ता, पीसीई और दिल्ली मंडल के अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि रेलवे ने त्योंहार के दौरान भारी भीड़भाड़ होने के बावजूद यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। श्री पांडे ने आगे अग्रगत कराते हुए कहा कि "यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा हमारी त्रिपाठी, मंडल रेल प्रबंधक, दिल्ली; श्री प्रवीण पांडे, पीसीसीएम, उत्तर रेलवे; श्री पंकज गंगवार, पीसीएससी/

यात्रियों की सुविधा के लिए रोज चलने वाली ट्रेनों के अलावा त्योंहार विशेष ट्रेनों भी चला रहा है।" उन्होंने भरोसा जताया कि रेलवे द्वारा की गई इन व्यापक व्यवस्थाओं से होली के त्योंहार के दौरान लाखों यात्रियों के लिए सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी। महाप्रबंधक ने अधिकारियों को यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाओं की निरंतर निगरानी तथा सुधार करने के निर्देश दिए।

गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर में एमडी (आयुर्वेद) के विद्यार्थियों को प्रेरक व्याख्यान देते हुए विश्व आयुर्वेद मिशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं आरोग्य भारती के साथ-साथ जीवनशैली जन्म जटिल एवं जीर्ण रोगों के उपचार में भी प्रभावी भूमिका निभा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयुर्वेद के सिद्धांत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिपादित स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं स्मार्ट फार्मा के वर्तमान युग में आयुर्वेदिक ज्ञान का नवोन्मेष करना समय की आवश्यकता है, तभी 'विकसित उत्तर प्रदेश' का संकल्प



के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. जी. एस. तोमर ने कहा कि आयुर्वेद अब भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व स्तर पर अपनी सशक्त पहचान स्थापित कर रहा है। डॉ. तोमर ने कहा कि भारतीय ज्ञान उन्होंने आगे कहा, यह हम दोनों के बीच तालमेल और आपसी भरोसे को दर्शाता है। कुछ महीने पहले जुलाई में

संरक्षण, संवर्धन, रोगोपशमन एवं प्रकृतिस्थापन जैसे चतुर्मुखी उद्देश्यों के पूर्णतः अनुरूप हैं। कोविड-19 कालखंड का उल्लेख करते हुए डॉ. तोमर ने बताया कि आयुर्वेदीय आयुष क्वाथ ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी असंख्य लोगों के जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि

साकार हो सकेगा। व्याख्यान के प्रारम्भ में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो. के. रामचन्द्र रेड्डी ने डॉ. तोमर का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए उनका परिचय प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में डॉ. रमाकांत, डॉ. लक्ष्मी सहित अनेक चिकित्सक, शिक्षक एवं विश्वविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे।

# पश्चिम बंगाल में नागरिकता आवेदनों के लिए विशेष समिति गठित, विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय का फैसला

# ब्राजील के राष्ट्रपति बोले- भारत में छठी बार आकर खुशी हो रही, गहरा करना होगा सहयोग

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकता से जुड़े आवेदनों की जांच और मंजूरी के लिए एक विशेष समिति बना दी है। गृह मंत्रालय ने 20 फरवरी 2026 को आदेश जारी कर बताया कि यह समिति नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके नियमों के तहत बनाई गई है। किसका आवेदन देखेगी समिति? यह समिति मुख्य रूप से उन लोगों के आवेदन देखेगी जो संशोधित कानून के तहत भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं। समिति की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल के जनगणना संचालन निदेशालय के डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल करेंगी। इसके अलावा इसमें खुफिया ब्यूरो, विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), डाक

विभाग और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। 'जांच, दस्तावेजों की पुष्टि, नागरिकता देने की सिफारिश का काम' सरकार ने बताया कि यह समिति

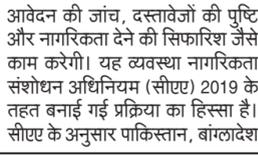
और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता पाने का रास्ता दिया गया है। नागरिकता आवेदनों की जांच प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से लंबी सीमा होने और यहां पहले से प्रवासियों के आने के कारण इसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। नई समिति बनने से अलग-अलग सरकारी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने शनिवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें भविष्य के लिए डिजिटल साझेदारी, दुर्लभ खनिज के क्षेत्र में सहयोग और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला में खनन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते शामिल हैं। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने क्या कहा? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा, 'मेरे प्रिय मित्र मोदी, यह मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं इस देश में छठी बार आया हूँ। भारत और ब्राजील की मुलाकात अद्वितीय है। हम केवल वैश्विक दक्षिण की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां नहीं हैं। यह एक डिजिटल महाशक्ति और एक नवीकरणीय ऊर्जा महाशक्ति की मुलाकात है। हम दोनों देश विविधता से भरपूर संस्कृतियों के केंद्र हैं और हम दोनों बहुपक्षीयता और शांति का

समर्थन करते हैं। उन्होंने बताया कि वह इस देश में आकर कितने खुश हैं। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे का जिक्र कर क्या कहा? उन्होंने आगे कहा, यह हम दोनों के बीच तालमेल और आपसी भरोसे को दर्शाता है। कुछ महीने पहले जुलाई में

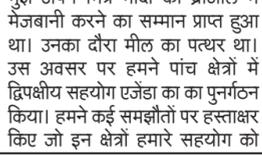
मजबूत गुणवत्ता प्रदान करते हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग पर क्या कहा? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा कि भारत और ब्राजील की आवाज खासकर बदलती भू-राजनीति के संदर्भ में अहम है। उन्होंने कहा कि अस्थिरता वाले वैश्विक माहौल में हमें अपनी रणनीतिक वार्ता को मजबूत और गहरा करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और जी20 में अहम हैं और हम एक अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा शासित बहुपक्षीय शासन की निर्माण में साझेदार हैं। राष्ट्रपति भवन में हुआ लूला डा सिल्वा का औपचारिक स्वागत इससे पहले दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। उनका राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें राष्ट्रपति भवन में गाई ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लूला ने उन्का स्वागत किया। राष्ट्रपति लूला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। शुक्रवार को राष्ट्रपति लूला ने नई दिल्ली में ब्राजीलियाई व्यापार और निवेश प्रोत्साहन एजेंसी (एपेक्स) के पहले कार्यालय का उद्घाटन किया। एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह ब्राजील के उत्पादों और सेवाओं को विदेश में बढ़ावा देने और ब्राजील की अर्थव्यवस्था के रणनीतिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा। लूला का भारत दौरा जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के ब्राजील दौरे के बाद हो रहा है, जो 50 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था।



एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ेगा और नागरिकता आवेदनों की जांच प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। बता दें कि, सीएए को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं।

मज्जे अपने मित्र मोदी को ब्राजील में मेजबानी करने का सम्मान प्राप्त हुआ था। उनका दौरा मील का पत्थर था। उस अवसर पर हमने पांच क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग एजेंडा का पुनर्गठन किया। हमने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो इन क्षेत्रों हमारे सहयोग को



हम एक अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा शासित बहुपक्षीय शासन की निर्माण में साझेदार हैं। राष्ट्रपति भवन में हुआ लूला डा सिल्वा का औपचारिक स्वागत इससे पहले दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र

महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल में, उन्होंने

# नौसेना प्रमुख ने बढ़ते समुद्री खतरों पर जताई चिंता, किया क्षेत्रीय एकता का आह्वान

# वो भारतवंशी, जिनकी दलीलों के सामने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टूट चुके चारों खाने चित

पणजी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने शनिवार को समुद्री खतरों से निपटने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) के देशों के बीच अधिक एकता का आह्वान किया। इन खतरों में, जिनमें समुद्री डकैती, अवैध प्रवासन और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समुद्र में आपराधिक नेटवर्क 'अधिक संगठित, तकनीकी रूप से जागरूक और परस्पर जुड़े हुए' हो गए हैं। उन्होंने ठोस नतीजे पाने के लिए सहयोगात्मक अभियानों की आवश्यकता पर जोर दिया। गोवा के नौसेना युद्ध महाविद्यालय में आयोजित गोवा समुद्री सम्मेलन (जीएमसी) के पांचवें संस्करण में समापन भाषण देते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि यह मंच संवाद-आधारित मंच से विकसित होकर कार्यवाहक-उन्मुख ढांचे में तब्दील हो गया है। द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन 'हिंद महासागर क्षेत्र में सामान्य समुद्री सुरक्षा चुनौतियां - गतिशील खतरों को कम करने के लिए प्रयासों की प्रगतिशील दिशाएं

(एलएसआई) विषय के तहत किया गया था। सम्मेलन में 14 देशों ने लिया हिस्सा

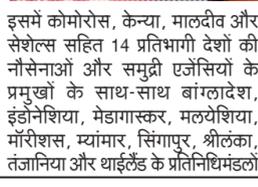
ने भाग लिया। प्रमुख सुरक्षा चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए नौसेना प्रमुख ने अवैध, बिना रिपोर्ट किए और अनियमित (फ्लॉट) मछली पकड़ने को प्राथमिक समुद्री खतरों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि आईएफसी (सूचना संलयन केंद्र)-इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलयेशिया, मॉरीशस, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड के प्रतिनिधिमंडलों

घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई है, जो बढ़ी हुई गश्त, बेहतर निगरानी और अधिक मजबूत प्रवर्तन के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है। अवैध रूप से मछली पकड़ना सबसे बड़ा समुद्री खतरा नौसेना प्रमुख ने कहा, 'हालांकि, उच्च मूल्य वाली प्रजातियों को लगातार निशाना बनाए जाने और अवैध शिकार की लगातार घटनाओं से कानूनी ढांचे, क्षेत्रीय सहयोग तंत्र, उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियों और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों को और मजबूत करने की आवश्यकता रेखांकित होती है।' उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन विशाखापत्तनम में हुए प्रमुख समुद्री आयोजनों के तुरंत बाद आयोजित किया गया, जिनमें अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा (आईएफआर), द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) के प्रमुखों का सम्मेलन शामिल हैं।

वांशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कानूनों को रद्द करके उन्हें उनके दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा झटका दिया। लेकिन ट्रंप को लगे इस झटके की जड़ में भारतीय मूल के एक वकील की दलीलें थीं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले में अहम भूमिका निभाई है, जिससे ट्रंप बेहद नाराज हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नील कात्याल की, जो अमेरिका के पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल और लेखक हैं। उन्होंने छोटे व्यवसायों के एक समूह का अदालत में प्रतिनिधित्व किया और अपने शब्दों में कहे तो 'पूर्ण और निर्णायक जीत' हासिल की। अमेरिकी टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले पर टिप्पणी करते हुए, कात्याल ने कहा कि इस

होते हैं, लेकिन अमेरिकी सिंधान उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। कात्याल ने ट्वीट किया, आज, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन और

महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल में, उन्होंने



इसमें कोमोरोस, केन्या, मालदीव और सेशेल्स सहित 14 प्रतिभागी देशों की नौसेनाओं और समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों के साथ-साथ बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलयेशिया, मॉरीशस, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड के प्रतिनिधिमंडलों

यही वजह है कि उन्होंने नाराज होकर कहा कि किसी भी टिप्पणी से पहले तथ्य जांच लेना चाहिए। मैक्रों ने यह भी कहा कि जो नेता खुद अपने देश के मामलों में



पूरे अमेरिका में नागरिकों के लिए आवाज उठाई है। अमेरिका में, केवल कांग्रेस ही अमेरिकी जनता पर कर लगा सकती है। कात्याल ने एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी प्रकाश डाला - राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नियुक्त तीन न्यायाधीशों में से दो ने इस मामले में उनके खिलाफ मतदान किया। नील कात्याल कौन हैं? 12 मार्च, 1970 को शिकागो में भारतीय-अमेरिकी माता-पिता प्रतिभा (डॉक्टर) और सुरेंद्र (इंजीनियर) के घर जन्मे नील कात्याल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर प्रतिष्ठित येल लॉ स्कूल में आगे की पढ़ाई की। कात्याल के करियर में

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 50 से अधिक मामलों की पैरवी की है। उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख मामलों में 1965 के मतदान अधिकाधिक अधिनियम की संवैधानिकता का बचाव करना और ट्रंप के 2017 के यात्रा प्रतिबंध को चुनौती देना शामिल है, जिसे हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। उनकी न्यायिक विशेषज्ञता के लिए उन्हें 2011 में अमेरिकी न्याय विभाग का सर्वोच्च न्यायिक सम्मान, एडमंड नॉल्डफ पुरस्कार मिला। वे फोर्ब्स की सूची में लगातार दो वर्षों (2024 और 2025) तक शामिल रहे हैं।

# हद में रहो...भारत से जाते ही मेलोनी से मैक्रों का हुआ तगड़ा झगड़ा! वजह जानकर चौंक जायेंगे

नई दिल्ली। वो कहावत है ना चिंगारी छोटी हो तो भी आग बड़ी बन सकती है और यूरोप की राजनीति में इस समय कुछ ऐसी ही चिंगारी दिख रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी के बीच अचानक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। खास बात यह है कि यह विवाद उस समय सामने आया जब मैक्रों भारत की यात्रा से लौट रहे थे। भारत दौरे के दौरान

दोनों देशों के नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की थी। लेकिन वापसी के समय मैक्रों का बयान सुर्खियों में आ गया। पत्रकारों ने जब उनसे मेलोनी के बयान पर सवाल पूछा, तो मैक्रों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हद में रहो बिना पूरी जानकारी के कुछ मत कहे। यहीं से यूरोप की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई। आखिर ऐसा हुआ क्या कि भारत से लौटते ही मैक्रों इतनी

तेजी से नाराज हो गए। क्या यह सिर्फ एक बयान है या फ्रांस और इटली के मौत से जुड़ा हुआ मामला था जिस पर दरअसल 17 से 19 तारीख तक मैक्रों भारत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा टेक्नोलॉजी और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई। लेकिन जब वे भारत से लौट रहे थे, उसी समय पत्रकारों ने उनसे

मेलोनी के एक बयान को लेकर सवाल पूछे। यह बयान फ्रांस में हुई एक मौत से जुड़ा हुआ मामला था जिस पर दरअसल 17 से 19 तारीख तक मैक्रों भारत के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा टेक्नोलॉजी और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई। लेकिन जब वे भारत से लौट रहे थे, उसी समय पत्रकारों ने उनसे

बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं उन्हें दूसरे देशों के मामले में बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अब समझिए पूरा मामला क्या है। दरअसल फ्रांस में हाल में 23 साल की दक्षिणपंथी कार्यकर्ता की मौत ने पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। यह घटना ल्यू शहर वेर एक विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुई।

होते हैं, लेकिन अमेरिकी सिंधान उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। कात्याल ने ट्वीट किया, आज, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन और

महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल में, उन्होंने